राष्ट्र एवं राज्य के प्रगति पथ पर...

रायपुर, दुर्ग एवं जगदलपुर से प्रकाशित

समय दर्शन

ESTD : Since 2011

संस्थापक : स्व. श्रीमती निलिमा खड़तकर

निष्पक्ष निर्भीक खबरों के साथ

वर्ष 15, अंक 137 | पृष्ठ 8, मूल्य 3.00 रूपये | दुर्ग, गुरूवार 09 अप्रैल 2026 | www.samaydarshan.in

संक्षिप्त समाचार

भारत ने ईरान में मौजूद भारतीयों को दी जल्द से जल्द देश छोड़ने की सलाह, युद्धविराम का स्वागत किया

नई दिल्ली। अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर समझौते के बावजूद, भारत ने बुधवार को ईरान में मौजूद अपने नागरिकों को सलाह दी कि वे जल्द से जल्द देश छोड़ दें। भारत ने अपने नागरिकों को ईरान में स्थित दूतावास के बताए रास्तों का इस्तेमाल करने का भी सुझाव दिया है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने बुधवार को एक एडवाइजरी में कहा, फ्र7 अप्रैल की एडवाइजरी के क्रम में और हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे दूतावास के साथ तालमेल बिठाकर और दूतावास की ओर से सुझाए गए रास्तों का इस्तेमाल करके जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें।फ्र भारतीय दूतावास ने आगे कहा, फ्रयह फिर से दोहराया जाता है कि दूतावास से पहले से सलाह और तालमेल किए बिना किसी भी अंतरराष्ट्रीय जमीनी सीमा तक पहुंचने की कोई कोशिश नहीं की जानी चाहिए।फ्र एडवाइजरी में दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए आपातकालीन नंबर भी शेयर किए हैं। हालांकि, एक ताजा पोस्ट में भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिका-ईरान के बीच युद्धविराम का स्वागत किया। इसके साथ ही, उम्मीद जताई कि इससे पश्चिम एशिया में स्थायी शांति स्थापित होगी।

भारतीय नौसेना का जहाज त्रिकंद केन्या के मोम्बासा पहुंचा

नई दिल्ली। भारतीय नौसेना का अग्रणी निर्देशित मिसाइल युद्धपोत आईएनएस त्रिकंद दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी जारी तैनाती के तहत केन्या के मोम्बासा पहुंचा। केन्या में इस तैनाती का उद्देश्य समुद्री सहयोग को मजबूत करना और भारत तथा केन्या के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना है।

इस बंदरगाह पर आईएनएस त्रिकंद युद्धपोत के आगमन के साथ ही पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन भी केन्या यात्रा पर पहुंचे।

इस यात्रा के दौरान व्यावसायिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों को आगे बढ़ाया जाएगा और आवश्यक सामग्री केन्या रक्षा बलों को सौंप दी जाएगी। इसके अलावा युद्धपोत के कमांडिंग ऑफिसर केन्या के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। मोम्बासा से प्रस्थान करने से पहले आईएनएस त्रिकंद केन्या नौसेना की इकाइयों के साथ एक पैसेज एक्सरसाइज (पासेक्स) में भाग लेगा। इस अभ्यास में सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों के आदान-प्रदान को सुगम बनाया जाएगा और द्विपक्षीय समुद्री अंतर संचालनीयता को बढ़ावा मिलेगा। आईएनएस त्रिकंद का मोम्बासा बंदरगाह पर आना भारत के महासागर (हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति) विजन के अनुरूप है।

200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुकेश चंद्रशेखर को मिली जमानत, कोर्ट ने लगाईं ये शर्तें

नई दिल्ली। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को 2 पत्ती चुनाव चिह्न रिश्वत कांड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी सुकेश चंद्रशेखर को 5 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि संविधान में व्यक्तिगत आजादी सबसे पवित्र अधिकारों में से एक है। ऐसे में अदालतें एक ओर आजादी की बात करें और दूसरी ओर सिर्फ विशेष कानूनों या आर्थिक अपराधों का हवाला देकर किसी आरोपी की स्वतंत्रता को अनावश्यक रूप से सीमित करें, यह सही नहीं है।

अदालत ने यह भी माना कि मनी लॉन्ड्रिंग एक गंभीर अपराध है और इसके लिए पीएमएलए जैसा विशेष कानून बनाया गया है। कोर्ट ने साफ कहा कि यह कानून राज्य के लिए ऐसा हथियार नहीं बन सकता, जिसके आधार पर किसी आरोपी की आजादी को लंबे समय तक दबाकर रखा जाए।

कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ कुल 31 मामले दर्ज होने के बावजूद इस केस में उनके जमानत के अधिकार को खत्म नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी माना कि वह इस मामले में पहले ही इतनी अवधि जेल में बिता चुके हैं, जो पीएमएलए की धारा 4 के तहत संभावित सजा की आधी अवधि से अधिक है। इसी आधार पर अदालत ने कहा कि उन्हें जमानत मिलना न्यायसंगत है।

कोर्ट ने दोहराया कि अपराध भले ही गंभीर हो, लेकिन कानून का इस्तेमाल किसी की आजादी को बेवजह लंबे समय तक रोकने के लिए नहीं किया जा सकता। इसलिए इस मामले में सुकेश चंद्रशेखर को जमानत दी गई है। फिलहाल सुकेश चंद्रशेखर जेल में ही रहेंगे, क्योंकि वे दूसरे मामले में अभी न्यायिक हिरासत में हैं। उनके खिलाफ कुल 31 मामले दर्ज हैं, जिनमें से 26 मामलों में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है।

सबरीमाला केस में सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल- ऐसी याचिकाओं पर सुनवाई क्यों हो

जो भक्त नहीं,वो धार्मिक परंपरा को चुनौती कैसे दे रहा- सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से पूछा कि जो लोग भगवान अयप्पा के भक्त नहीं हैं, वे केरल के सबरीमाला मंदिर की परंपराओं को कैसे चुनौती दे सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे पर 7 सवाल तय किए हैं। इनमें से एक सवाल यह है कि क्या कोई व्यक्ति, जो किसी धार्मिक संप्रदाय या समूह से संबंधित नहीं है, उस 'धार्मिक संप्रदाय या समूह' की किसी प्रथा को जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दे सकता है।

जस्टिस बीवी नागरत्ना ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि सबरीमाला मामले में याचिकाकर्ता कौन थे। 'मूल याचिकाकर्ता भक्त नहीं थे। किसी भी भक्त ने इस प्रथा को चुनौती देने के लिए अदालत का रुख नहीं किया। तो फिर ये रिट याचिकाकर्ता कौन हैं जो इसे चुनौती दे रहे हैं।'

मेहता ने जवाब दिया कि मूल याचिकाकर्ता 'इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन' नामक वकीलों का एक संगठन है।

न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा, वे भक्त नहीं हैं। लेकिन हमें यह स्पष्ट करना होगा। क्या भगवान अयप्पा का कोई भी भक्त इस परंपरा को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर कर सकता है और यदि कोई गैर-भक्त, जिसका उस मंदिर से कोई संबंध नहीं है, इसे चुनौती देता है, तो क्या यह अदालत ऐसी याचिका पर सुनवाई कर सकती है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा- कोई सेक्युलर अदालत किसी धार्मिक प्रथा को सिर्फ अंधविश्वास नहीं कह सकती, क्योंकि उसके पास ऐसा तय करने की विशेषज्ञता नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो चीज नगालैंड के किसी समुदाय के लिए धार्मिक हो सकती है, वही मेरे लिए अंधविश्वास लग सकती है। हमारा समाज विविधतापूर्ण है, यहां अलग-अलग लोग, धर्म और मान्यताएं हैं। ऐसे में अदालत के लिए ऐसा फैसला खतरनाक हो सकता है।

जस्टिस अमानुल्लाह ने इस पर कहा, मिस्टर मेहता, आपने बात को बहुत आसान बना दिया है। अदालत के पास न्यायिक समीक्षा का अधिकार है कि वह यह तय कर सके कि अंधविश्वास क्या है। उसके बाद उस पर कानून बनाना या कार्रवाई करना विधानमंडल (संसद-विधानसभा) का काम हो सकता है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि अंतिम फैसला सिर्फ विधायिका ही करेगी। धर्म के मामलों में तर्क उसी तरह लागू नहीं किया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला महिलाओं के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के संतुलन से जुड़ा है। कोर्ट ने सती प्रथा, जादू-टोना और नरभझी के उदाहरण दिए और कहा कि अगर कोई प्रथा समाज को झकझोरती है, तो अदालत हस्तक्षेप कर सकती है।

जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि अदालत को यह देखना होगा कि कोई प्रथा उस धर्म के लिए जरूरी है या नहीं। यह जांच उसी धर्म की सोच और परंपरा के आधार पर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी दूसरे धर्म के नजरिए से यह तय नहीं किया जा सकता कि कोई प्रथा जरूरी है या नहीं। लेकिन यह सब सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के दायरे में होना चाहिए।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 1972 के फैसले में पालखीवाला के तर्क पढ़े कि सामाजिक सुधार के बहाने राज्य किसी धर्म को मिटा नहीं सकता। इस पर जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि सामाजिक सुधार के नाम पर कोई धर्म अपनी पहचान नहीं खो सकता। मेहता ने कहा कि सुधार के नाम पर धर्म के मूल तत्व का बलिदान नहीं किया जा सकता। धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ भेदभाव का मामला बीते 26 सालों से देश की अदालतों में हैं। 2018 में, 5 जजों की बेंच ने 4:1 के बहुमत से मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक हटा दी थी।

'चुनाव आयोग पहुंचे तृणमूल नेताओं को सात मिनट में भगाया गया'; डेरेक ओ ब्रायन ने लगाए गंभीर आरोप

नई दिल्ली(एजेंसी)। टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने आज दिल्ली में चुनाव आयोग के समक्ष अपनी नाराजगी व्यक्त की। सांसद का आरोप है कि आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त (ष्टश्वष्ट) ने उनसे केवल सात मिनट में बैठक खत्म कर हट जाने को कहा।

डेरेक ओ ब्रायन ने बताया आज हम मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने गए। बैठक सुबह 10:02 बजे शुरू हुई। जब हमने उनसे पूछा कि आप अधिकारियों के तबादले कैसे कर रहे हैं और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कैसे करवाएंगे, बैठक के सात मिनट के भीतर ही उन्होंने कहा 'यहां से दफा हो जाओ।' जो मैंने आज देखा, वह शर्मनाक है।

सांसद ने आगे चुनौती दी कि चुनाव आयोग वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी करे, जिससे स्पष्ट हो सके कि बैठक में वास्तव में क्या हुआ। डेरेक ओ ब्रायन ने कहा हमारे एक सहयोगी ने उन्हें भारत के एकमात्र ष्टश्वष्ट होने पर बधाई दी जिन पर लोकसभा और राज्यसभा से हटाने के नोटिस आए हैं। इस मुद्दे पर आज सभी समान विचारधारा वाले विपक्षी दल शाम 4 से 4:30 बजे तक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।

चुनाव आयोग का टीएमसी को अल्टीमेटम

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस बार पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण होंगे। आयोग ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि चुनाव भयमुक्त, हिंसा रहित, धमकियों से मुक्त, लालच रहित होंगे। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि किसी भी तरह की छापेमारी, बूथ जामिंग या स्रोत जामिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

आम आदमी को महंगे लोन से नहीं मिलेगी राहत, आरबीआई ने रेपो रेट में नहीं किया बदलाव

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2026 की मौद्रिक नीति के फैसले की घोषणा कर दी, जिसमें रेपो रेट को 5.25 फीसदी पर बरकरार रखने का फैसला लिया गया। संभावना जताई जा रही थी कि इस बार भी दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। फिलहाल रेपो रेट 5.25 फीसदी रहेगी। यह निर्णय बाजार की उम्मीदों के अनुरूप रहा और छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने दो दिनों की चर्चा के बाद सर्वसम्मति से इसे मंजूरी दी। आरबीआई के इस फैसले का उद्देश्य मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच आर्थिक स्थिरता बनाए रखना है।

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने नीतिगत निर्णय की घोषणा करते हुए कहा कि बैंक दर और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (एमएसएफ) की दर 5.50 प्रतिशत पर यथावत रखी गई है, जबकि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (एसडीएफ) की दर भी 5.00 प्रतिशत पर बरकरार है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब वैश्विक स्तर पर आर्थिक हालात लगातार चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं।

आरबीआई गवर्नर ने 2025 को एक चुनौतीपूर्ण वर्ष बताया, लेकिन यह भी कहा कि अक्टूबर की नीति के बाद से मुद्रास्फीति में कमी आई है। उन्होंने बैंकिंग प्रणाली की बेहतर कार्यकुशलता को अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रमुख सहारा बताया। गौरतलब है कि यह घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के साथ दो सप्ताह के युद्धविराम की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद हुई। इस घटनाक्रम से वैश्विक बाजारों में सकारात्मक माहौल बना और भारतीय शेयर बाजार में भी तेजी देखने को मिली।

आरबीआई गवर्नर ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। हालांकि उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताएं, खासकर पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की ऊंची कीमतें, भारत की विकास दर पर दबाव डाल सकती हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि बाहरी कारक भारत की आर्थिक गति के लिए प्रमुख जोखिम बने हुए हैं।

भारत-पाक बॉर्डर पर 200 मीटर तक फेंसिंग शिफ्ट, पंजाब के 6 सरहदी जिलों में होगा भूमि अधिग्रहण

चंडीगढ़ (एजेंसी)। भारत-पाक सीमा पर फेंसिंग को करीब 200 मीटर तक शिफ्ट किए जाने के मामले में बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया है। इस कदम के तहत पंजाब के छह सरहदी जिलों में भूमि अधिग्रहण किया जाएगा, जिससे सीमा सुरक्षा के साथ-साथ स्थानीय विकास को भी गति मिलने की उम्मीद है। सरकार ने इस प्रक्रिया को तेज और सरल बनाने के लिए अहम बदलाव किए हैं। अब भूमि अधिग्रहण से जुड़े सभी अधिकार सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (स्ष्ठरू) को सौंप दिए गए हैं। स्ष्ठरू को कलेक्टर की शक्तियां दी गई हैं, जिससे मुआवजा तय करने, पुनर्वास और अन्य प्रशासनिक फैसले जिला स्तर पर ही लिए जा सकेंगे।

अधिकारियों के अनुसार, इस निर्णय से किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। पहले जहां मुआवजा और पुनर्वास के लिए लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, वहीं अब फैसले स्थानीय स्तर पर तेजी से होंगे। इससे प्रभावित किसानों को समय पर मुआवजा और पुनर्वास सुविधाएं मिलने की संभावना बढ़ेगी।

सरहदी इलाकों में रहने वाले किसानों के लिए यह फैसला राहत भरा माना जा रहा है। प्रशासन का दावा है कि नई व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और भूमि अधिग्रहण से जुड़े विवाद भी कम होंगे।

अमरावती बनी आंध्र प्रदेश की स्थायी राजधानी, सीएम चंद्रबाबू नायडू ने किया ऐलान

अमरावती (एजेंसी)। आंध्र प्रदेश के लोगों का अपनी स्थायी राजधानी को लेकर बरसों पुराना इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। अमरावती को अब आधिकारिक तौर पर आंध्र प्रदेश की एकमात्र और स्थायी राजधानी घोषित कर दिया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (ङ्ग) पर इस ऐतिहासिक फैसले की जानकारी साझा की है। सीएम नायडू ने आधिकारिक अधिसूचना को शेयर करते हुए गर्व के साथ स्पष्ट किया, 'आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है।' बता दें कि हाल ही में संसद के बजट सत्र के दौरान 'आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम संशोधन विधेयक 2026' को दोनों सदनों में भारी बहुमत से पारित किया गया था, जिसके बाद यह रास्ता पूरी तरह से साफ हुआ है।

'बरसों पुराना सपना हुआ साकार', ष्टरूनायडू ने जताया राष्ट्रपति और पीएम मोदी का आभार

इस ऐतिहासिक और भावुक क्षण पर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने खुशी जताते हुए देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का विशेष रूप से धन्यवाद किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि आंध्र प्रदेश के करोड़ों लोगों की ओर से वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु जी का दिल से आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने इस संशोधन अधिनियम, 2026 को अपनी अंतिम मंजूरी दी। नायडू ने कहा कि इस मुहर के साथ ही हमारी अपनी राजधानी का पुराना सपना अब हकीकत में बदल गया है। उन्होंने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी विशेष आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने राज्य के लिए किया अपना वादा निभाया और लगातार सही मार्गदर्शन दिया।

खत्म हुआ राजधानी का असमंजस, विकास की दिशा में एक निर्णायक कदम

सीएम नायडू के नेतृत्व वाली टीडीपी-एनडीए (ञ्जष्ठक्क-हृष्ठ) सरकार की इस बड़ी सफलता को अमरावती के भविष्य और राज्य के सुनहरे कल के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। गौरतलब है कि जब आंध्र प्रदेश का तेलंगाना से विभाजन हुआ था, तब चंद्रबाबू नायडू ने ही अमरावती को राज्य का नया प्रशासनिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र बनाने की भव्य योजना तैयार की थी। बीच में सत्ता परिवर्तन और अन्य कारणों से राजधानी को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई थी, लेकिन अब यह पूरी तरह साफ हो गया है कि राज्य की तीन नहीं बल्कि सिर्फ एक ही राजधानी होगी और वह अमरावती होगी। इस फैसले से न सिर्फ राज्य में प्रशासनिक स्पष्टता आई है, बल्कि इसे निवेश और विकास की दिशा में भी एक बेहद निर्णायक कदम माना जा रहा है।

ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमला कर उसके परमाणु कार्यक्रमों को दशकों पीछे पहुंचा दिया

अमेरिका-इजरायल-ईरान ने किया युद्धविराम

नई दिल्ली (एजेंसी)। अमेरिका और ईरान ने दो हफ्ते के युद्ध विराम की घोषणा की है. इस युद्ध विराम में इजरायल भी शामिल है. युद्ध विराम समझौते की शर्तें अभी सार्वजनिक नहीं हुई हैं. लेकिन अभी दोनों पक्ष इसे अपनी-अपनी जीत बता रहे हैं. लेकिन यह सत्य है कि इस युद्ध में दोनों पक्षों को जान-माल का भारी नुकसान उठाना पड़ा है.

अमेरिका और इजरायल ने ईरान में सत्ता परिवर्तन के उम्मीद से हमला किया था. उन्हें उम्मीद थी कि आयतुल्लाह अली खामेनेई के निधन के बाद ईरान बिखर जाएगा और वो अपनी कठपुतली सरकार वहां बैठा पाने में कामयाब होंगे. लेकिन ऐसा वहां नहीं हो पाया. खामेनेई के निधन के बाद भी ईरान पूरी ताकत के साथ अमेरिका और इजरायल से लड़ा. वहां कोई नागरिक विद्रोह भी नहीं हुआ. ऐसे में अमेरिका और इजरायल ईरान में अपना लक्ष्य हासिल कर पाने में कामयाब नहीं हो पाए. वहीं ईरान की बात करें तो उसने अमेरिका और इजरायल के खिलाफलड़ाई लड़ी. उसने इजरायल और खाड़ी के देशों में अमेरिकी ठिकानों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया. यह ईरान के लिए एक तरह से जीत की ही तरह है. हालांकि उसे काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है. अमेरिका और इजरायल ने ईरान के रणनीतिक महत्व के केंद्रों और ऊर्जा संसाधनों पर बमबारी कर उन्हें तबाह कर दिया. इसके साथ ही दोनों ने ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमला कर उसके परमाणु कार्यक्रमों को दशकों पीछे पहुंचा दिया है. यह ईरान के लिए एक तरह से हार की तरह है.

किसे कितना हुआ नुकसान

मिडिल ईस्ट में करीब 40 दिन तक चला यह युद्ध नुकसान के लिए भी जाना जाएगा. दोनों तरफ को सैन्य साजो-सामान का भारी नुकसान उठाना पड़ा है. लेकिन अगर इसे लागत के नजरिए से देखेंगे तो अमेरिका और इजरायल घाटे में दिखाई देंगे. इस युद्ध में ईरान ने अमेरिका के एफ-15 और एफ-35 जैसे उन्नत लड़ाकू विमानों, हवा में विमानों में ईंधन भरने वाले केसी-135 विमान, कई तरह के हेलिकॉप्टर इस युद्ध में तबाह हो गए. एफ-15 और एफ-35 को अमेरिका दुनिया के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान कहकर बेचता है. लेकिन ईरान ने उन्हें अपने सस्ते ड्रोन से ही उन्हें निशाना बना दिया. इससे इन विमानों को लेकर बनाई गई छवि को गहरा धक्का लगा है. अमेरिका अब इन विमानों को अपराजेय बताकर नहीं बेच पाएगा.

इसके अलावा इस युद्ध में अमेरिका और इजरायल की हवाई सुरक्षा प्रभाणी भी उतनी असरदार नजर नहीं आई, जैसा कि दावा किया जा रहा था. ईरान ने शाहेद नाम के अपने सस्ते ड्रोन इजरायल और खाड़ी के देशों में उड़ाए उसे इंटरसेप्ट और हवा में ही निष्क्रिय करने के लिए अमेरिका और इजरायल को अपनी महंगी मिसाइले और एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय करना पड़ा.

इसके बाद भी ईरान के बहुत से शाहेद ड्रोन अपने लक्ष्यों को भेदने में कामयाब रहे. इस वजह से अब अमेरिका की एयर डिफेंस प्रणाली थॉड और इजरायल की एयर डिफेंस प्रणाली आयरन डोम की विश्वसनीयता को लेकर दुनिया में संदेह पैदा हुआ है. इसके विपरीत पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' में भारत के स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम और रूसी एस-400 ने काफी सटीक काम किया था.

ग्रामीण बैंक का प्रिंटर खराब होने से खाता धारकों को हो रही भारी परेशानी

बिर्रा (समय दर्शन)। चांपा रोड में स्थित छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक शाखा बिर्रा का प्रिंटर खराब होने से खाता धारकों को खाता में प्रिंट करवाने एवं नई पासबुक बनवाने और नया खाता खुलवाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

गौरतलब है कि जांजगीर चांपा जिला के जनपद पंचायत बम्हनीडीह के अंतर्गत ग्राम पंचायत बिर्रा में स्थित छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक शाखा बिर्रा में प्रिंटर खराब होने से खाता धारकों को अपने बैंक खाता (पासबुक) में प्रिंट करवाने एवं पुराना बैंक खाता को नई बैंक खाता बनवाने और नया खाता खुलवाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मजेदार बात यह है कि बैंक प्रबंधन को खाता धारकों के परेशानियों से कोई लेना-देना नहीं है हालात जस की तस बनी हुई है। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक शाखा बिर्रा में पदस्थ कैशियर शिखा शुक्ला के तेंवर चरम सीमा के सातवें आसमान पर टिकी है। अपने ड्यूटी को बैंक प्रबंधन के नियम के अनुसार न करते हुए ड्यूटी समय में मोबाइल चलाती रहती है। यहां पर बात रुपए जमा करने या रुपए निकालने के लिए बोलने पर खाता धारकों से झींक झींक हमेशा करती रहती है, अर्थात उच्च स्वर में खाताधारकों से बेहूदा बात करती है। जिसके कारण खाता धारकों को घंटों तक लाइन में लगकर अपनी बारी आने का इंतजार करना पड़ रहा है।

बहरहाल कारण चाहे जो भी हो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक शाखा बिर्रा में प्रिंटर खराब होने से और कैशियर शिखा शुक्ला के अड़ियल रवैया से उनके क्रियाकलाप और कार्य शैली से खाता धारकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

खबर-खास

कठिन साधना में बैठे गुरू निर्वाण अनंतानंद उदासीन

राजनांदगांव (समय दर्शन)। गुरू निर्वाण अनंतानंद उदासीन जी महराज इन दिनों एक कठिन साधना कर रहे हैं। बैसाख (अप्रैल) की तपती दोपहरी में खुले में वह पँचधुना साधना करने आसन लगा रहे हैं।

गुरूजी बताते हैं कि यह साधना वह जनकल्याण की भावना को लेकर कर रहे हैं। कुल 41 दिनों की यह साधना डोंगरगाँव मार्ग पर स्थित श्री कल्याणिका देवस्थानम नामक मंदिर आश्रम में की जा रही है।

बाबाजी कल्याण आश्रम राजनांदगांव में यह साधना 2 अप्रैल से की जा रही है, यह धार्मिक कार्य 12 मई तक अनवरत चलेगा। प्रतिदिन दोपहर 11 बजे वह साधना में बैठते हैं। इसका समापन रोजाना साढ़े बारह बजे होता है।

गुरूजी के शब्दों में उन्हें ऐसी कठिन साधना की प्रेरणा मां भगवती सहित अपने गुरु परम तपस्वी बाबा कल्याण दास जी महाराज के आशीर्वाद से मिली। वह प्रतिदिन पाँच स्थानों पर कंडों को प्रज्वलित कर उनके मध्य में साधनारत होते हैं।

उड़ीसा से गांजा लेकर आ रहे स्विफ्ट डिजायर कार से 62 किलो 245 ग्राम गांजा बरामद

सारँगढ बिलाईगढ़(समय दर्शन)। जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के पुलिस अधीक्षक आंजनेय वार्ष्णेय के द्वारा जिले के सभी थाना/चौकी प्रभारियों को जुआ, सट्टा, शराब, अवैध मादक पदार्थ गांजा में संलिप्त व्यक्तियों पर कड़ी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने पर अति0 पुलिस अधीक्षक श्रीमती निमिषा पाण्डेय एवं उप पुलिस अधीक्षक सुश्री संतोषी ग्रेस के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी प्रमोद यादव के कुशल नेतृत्व मे सरिया पुलिस को अवैध गांजा परिवहन करते स्विफ्ट डिजायर कार से 62 किलो 245ग्राम मादक पदार्थ गांजा बरामदकरने में सफलता प्राप्त हुई है।

विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 07/08/2026को दौरान पेट्रोलिंग जरिये मुखबीर सुचना मिला कि एक सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार में कुछ व्यक्ति उड़ीसा से गांजा लेकर शक्ति -जांजगीर तरफ जाने वाले है सूचना पर ग्राम बोरिदा ,बगीचा तालाब पास मेन रोड मे घेराबंदी करने पर स्विफ्ट डिजायर कार का चालक कार को दूर में छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया।गवाहों के समक्ष स्विफ्ट डिजायर कार की तलाशी लेने पर कार के अंदर 59 पैकेट में कुल 62 किलो 245 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा मिला। मौके पर 62 किलो 245 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा, 01नग स्विफ्ट डिजायर कार को जप्त कर अज्ञात कार चालक के खिलाफ थाना सरिया मे अपराध क्रमांक 71/2026 धारा 20 बी एनडीपीएस एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी प्रमोद यादव ,सउनि मोतीलाल डनसेना, प्र0आर0- विजय यादव ,मोहन गुप्ता आर ,विमल जांगड़े, खेमलाल श्रवण टंडन दिलीप स्नेही, दिगंबर ,दिलीप साव, साइबर सेल से रामकुमार मानिकपुरी,दीपक मैत्री, कृष्णा डनसेना,मोतीलाल जांगड़े व समस्त थाना स्टाफ का विशेष योगदान रहा।

छुईपाली के प्रभारी बने विजय बंजारे

सरायपाली (समय दर्शन)। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन में विजय बंजारे को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी छुईपाली का प्रभारी बनाया गया है। प्रभारी बनाए जाने पर पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए द्वारकाधीश यादव (जिला अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी महासमुंद), देवेन्द्र बहादुर सिंह (राजा साहब, पूर्व विधायक बसना), श्रीमती चातुरी नंद विधायक सरायपाली,वरिष्ठ नेता मंजीत सिंह छाबड़ा, तौकीर सरवर दानी,अनंत सिंह वर्मा, मुकेश यादव पूर्व उपाध्यक्ष जनपद पंचायत पिथौरा,करण सिंह दीवान अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी पिथौरा, आत्माराम यादव पूर्व अध्यक्ष नगर पंचायत पिथौरा,इश्तियाक खेरानी, महेंद्र नायक,रवि कश्यप ,नोविना जगत, धर्मेंद्र सिदार, पूरन पटेल, जितेन्द्र सिदार,खालिद दानी, हेमन्त कौशिक,मोनू खेरानी,बेदराम कुर्रे ,सहित सभी वरिष्ठ नेताओं का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित किया। विजय बंजारे ने कहा कि पार्टी द्वारा उन पर जताए गए विश्वास पर खरा उतरते हुए वे संगठन को मजबूत बनाने, जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता देने तथा कांग्रेस की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने के लिए पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ कार्य करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर क्षेत्र में संगठन को और अधिक सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे। विजय बंजारे के छुईपाली प्रभारी बनने पर क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों में हर्ष का माहौल है।

भाजपा का गांव/बस्ती चलो अभियान, ग्राम अंडोंला पहुंचे भाजपा नेता हरिनाथ खुटे

सारंगढ़ बिलाईगढ़। (समय दर्शन)भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर चलाए जा रहे गांव/बस्ती चलो अभियान के अंतर्गत जिला भाजपा के निर्देशानुसार कोसीर मंडल के ग्राम पंचायत अंडोला की बस्ती में जनसंपर्क अभियान चलाया गया।

बता दे कि जिला भाजपा सारंगढ़ बिलाईगढ़ के द्वारा कोसीर मंडल के ग्राम अंडोंला में प्रदेश महामंत्री अजा मोर्चा श्री हरिनाथ खुटे को प्रवास हेतु निर्धारित किया गया।

इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों एवं लाभार्थियों से मुलाकात कर केंद्र की मोदी सरकार एवं छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सुशासन सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से बताते हुए योजनाओं का लाभ उठाने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने भी अपने अनुभव साझा किए और सरकार द्वारा मिल रहे लाभों के प्रति संतोष व्यक्त किया

उक्त कार्यक्रम में हरिनाथ खुटे प्रदेश महामंत्री अजा मोर्चा, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा हितेश अजगल्ले, मंडल महामंत्री शिवम चंद्रा, मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा कोसीर नोहर साहू, जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा गुणसागर साहू, श्रीमती लाकेश्वरी चन्द्रा, इंद्रिका चन्द्रा, जिला सोशल मीडिया सह प्रभारी अभिषेक पटेल सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

फॉग मशीन मॉडल' से जंगल सुरक्षित: डीएफओ ने खुद थामी मशीन

आगजनी की घटनाओं में आई 80 फीसदी की कमी

महासमुन्द (समय दर्शन)। गर्मियों के मौसम में हर साल बढ़ने वाली आगजनी की घटनाओं पर इस बार महासमुंद वन विभाग ने प्रभावी नियंत्रण पा लिया है। खेतों में पराली जलाने या झाड़ियों में लगाई गई आग अक्सर जंगलों तक पहुंचकर भारी नुकसान करती थी, लेकिन इस बार विभाग की नई रणनीति और जमीनी सक्रियता से हालात बदलते नजर आ रहे हैं।

इस अभियान की अगुवाई कर रहे डीएफओ मयंक पांडेय खुद मैदान में उतरकर आग बुझाने का काम कर रहे हैं। खास बात यह है कि वे अपनी गाड़ी में फॉग (स्नहल) मशीन रखते हैं, और जैसे ही कहीं आग लगने की सूचना मिलती है, तत्काल मौके पर पहुंच जाते हैं। उनके साथ उनका ड्राइवर भी इस मुहिम में सक्रिय सहयोग करता है। इस मुहिम में बसना,पिथौरा रेंजर सुखराम निराला, सरायपाली रेंजर प्रत्युष ताण्डे भी सकारात्मक सहयोग करते हुए इस पहल से वन को बचाने में दिशानिर्देश का पालन कर रहे हैं।

वन विभाग की इस तत्परता का असर साफ दिखाई दे रहा है। साल 2026 में 15 फरवरी से 7 अप्रैल तक आगजनी की घटनाओं में करीब 80 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। जहां पिछले साल 2025 में कुल 284 घटनाएं सामने आई थीं, वहीं इस साल यह संख्या काफी घट गई है।

जंगल और वन्यजीवों पर बड़ा खतरा

महुआ इकट्ठा करने के लिए लगाई जाने वाली आग जंगलों के लिए सबसे बड़ा खतरा बनती जा रही है। इससे न सिर्फ पेड़-पौधे नष्ट होते हैं, बल्कि हिरण, तेंदुआ, भालू, जंगली सूअर और पक्षियों जैसे वन्यजीव भी बेघर हो जाते हैं। इन हालातों से निपटने के लिए वन विभाग का मैदानी अमला दिन-रात डटा हुआ है और कई बार अपनी जान जोखिम में डालकर आग पर काबू पाता है।

वन विभाग ने 15 फरवरी से 15 अप्रैल तक नो फायर अभियान चलाया है। इसके तहत 150 चौकीदार, 70 बीट गार्ड, 25 डिप्टी रेंजर व रेंजर (महिलाएं भी शामिल), तैनात किए गए हैं। आग बुझाने के लिए 101 फायर ब्लोअर दिए गए थे, लेकिन कमी को देखते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर 19 अतिरिक्त ब्लोअर खरीदे। साथ ही जूते और टॉर्च जैसी सुविधाएं देकर कर्मचारियों को 24 घंटे अलर्ट रखा गया है।

वनमंडलाधिकारी ने ओडिशा के नुआपड़ा और बरगढ़ वन अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर संयुक्त रणनीति तैयार की है। सरायपाली क्षेत्र में पहाड़ी और घने जंगल की सीमा उड़ीसा से सटे होने के कारण यहां आगजनी की घटनाएं अधिक होती हैं, जिस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

पिरदा मंडल में भाजपा का 47वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया

बसना (समय दर्शन)। भारतीय जनता पार्टी का 47वां स्थापना दिवस पिरदा मंडल में बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा ध्वजारोहण किया गया तथा आतिशबाजी और मिठाई वितरण कर खुशियां मनाई गई।कार्यक्रम की शुरुआत पार्टी के महान नेताओं डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के तेलचित्र पर पुष्प अर्पित कर की गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनके विचारों को याद करते हुए विकसित भारत के निर्माण हेतु एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प लिया।

भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा ध्वजारोहण, आतिशबाजी और पुष्पांजलि के साथ कार्यकर्ताओं ने लिया राष्ट्र निर्माण का संकल्प।

कार्यकर्ताओं ने भाजपा के संघर्ष से सिद्धि तक के सफर को याद करते हुए कहा कि एक समय छोटी शुरुआत करने वाली पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में स्थापित हो चुकी है। राष्ट्र प्रथम, पार्टी द्वितीय और हम अंतिम के सिद्धांत पर चलने वाली भाजपा ने देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है।

कार्यक्रम में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रसिद्ध पंक्तियों अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा को भी याद किया गया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि आज यह भविष्यवाणी सच होती नजर आ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार प्रगति कर रहा है।इस दौरान भाजपा सरकार की उपलब्धियों, जैसे कश्मीर से धारा 370 हटाना और अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण, को भी रेखांकित किया गया।

कार्यक्रम में मुख्य रूप से हर प्रसाद पटेल (उपाध्यक्ष जिला महासमुंद), श्रीमती सीमा नायक (उपाध्यक्ष महिला मोर्चा जिला एवं सभापति महासमुंद), अभिमन्यु प्रधान (मंडल अध्यक्ष), हेमलाल सिदार (महामंत्री अ.ज.जा. मोर्चा महासमुंद), मनीराम निषाद (महामंत्री), सुभाष बंजारा (महामंत्री), परशुराम गढ़तिया (जिला कार्यसमिति सदस्य), श्रीमती विमला बेहरा (अध्यक्ष महिला मोर्चा एवं जनपद सदस्य पिथौरा), इंदल साव (उपाध्यक्ष), तोष कुमार पटेल (उपाध्यक्ष), मकरध्वज भोई (मंत्री), आमोश दीप (मीडिया प्रभारी), सुरेश नायक (अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा), बाबूलाल नेटी (अध्यक्ष अ.ज.जा. मोर्चा), राजकुमार चौहान (अध्यक्ष अ.जा. मोर्चा) एवं दिनेश कश्यप (अध्यक्ष भाजयुमो) उपस्थित रहे।

इसके अलावा हेतराम राठौर (महामंत्री पिछड़ा वर्ग मोर्चा), उत्तर कुमार पटेल (महामंत्री पिछड़ा वर्ग मोर्चा), रूपानंद नायक (उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा), श्रीमती पंच बाई नंद (उपाध्यक्ष महिला मोर्चा), श्रीमती पदमा रातडे (महामंत्री महिला मोर्चा), श्रीमती रीना प्रधान (महामंत्री महिला मोर्चा), श्रीमती चंचल सोना (प्रवक्ता महिला मोर्चा), दाशरथी चौहान (महामंत्री अ.जा. मोर्चा), सोनसाय खूटे (महामंत्री अ.जा. मोर्चा), गुलाब निषाद (उपाध्यक्ष किसान मोर्चा), मोहन पटेल (अध्यक्ष पिरदा सोसायटी), खिरसाय पटेल (पूर्व उपाध्यक्ष), संदीप साहू (महामंत्री भाजयुमो) एवं सुखसागर बरिहा (महामंत्री अ.ज.जा. मोर्चा) सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।

वहीं सेतकुमार चौहान (उपाध्यक्ष अ.जा. मोर्चा), दिनेश खूटे (उपाध्यक्ष अ.जा. मोर्चा), बिहारी खूटे (मंत्री अ.जा. मोर्चा), रोहित सिदार (उपाध्यक्ष अ.ज.जा. मोर्चा), कन्हैया पारेश्वर (मीडिया प्रभारी अ.ज.जा. मोर्चा), राजाराम परमार (उपाध्यक्ष भाजयुमो), ज्ञान चंद प्रधान (उपाध्यक्ष भाजयुमो), प्रकाश सेठ (मीडिया प्रभारी पिछड़ा वर्ग मोर्चा), बंशीधर पटेल (उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा), दुलसिंह यादव (शक्ति केंद्र प्रभारी), गजेंद्र भोई (बूथ अध्यक्ष), नरेश पटेल (जिला कार्यकारिणी सदस्य भाजयुमो), जगतराम कुमार (उपाध्यक्ष अ.जा. मोर्चा), श्रीमती सुरेंद्री गढ़तिया (महिला मोर्चा), श्रीमती नमिता प्रधान (महिला मोर्चा) एवं खेमराज सोना सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

कृषि विभाग की कार्यवाही निजी कृषि केंद्रों में बिक्री पर लगी रोक

अनियमितता पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी

बिलासपुर (समय दर्शन)। खरीफ सीजन 2026 को देखते हुए किसानों को खाद, बीज और कीटनाशकों की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी और वितरण में गड़बड़ी रोकने के उद्देश्य से जिला एवं विकासखंड स्तर पर उड़नदस्ता दल का गठन कर औचक निरीक्षण किया जा रहा है।

इसी कड़ी में उड़नदस्ता दल ने आज विकासखंड मस्तूरी के जोंधरा क्षेत्र में संचालित कृषि केंद्रों की जांच के दौरान गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। मेसर्स प्रजापति खाद भंडार में बिल और वास्तविक वितरण में अंतर, स्टॉक और दर प्रदर्शित नहीं करना तथा आवश्यक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने जैसे उल्लंघन पाए गए। इसके चलते प्रतिष्ठान को कारण बताओ नोटिस जारी कर 21 दिनों के लिए उर्वरक विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसी तरह मेसर्स चंदेल ट्रेडर्स में भी स्टॉक और दर प्रदर्शित नहीं करना, निर्धारित प्रारूप में बिल जारी न करना तथा बिना पॉस मशीन के उर्वरक विक्रय जैसी अनियमितताएं पाई गईं। इस पर भी 21 दिनों के लिए बिक्री पर रोक लगाई गई है। संभागीय संयुक्त संचालक कृषि ने अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देश दिए हैं कि किसानों को निर्धारित दर पर गुणवत्तायुक्त उर्वरक उपलब्ध कराया जाए और किसी भी प्रकार की कालाबाजारी या जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि उर्वरक का वितरण केवल पॉस मशीन के माध्यम से ही किया जाएगा और स्टॉक में गड़बड़ी मिलने पर तत्काल कार्रवाई होगी। जिले में हर विकासखंड के लिए 4 सदस्यीय उड़नदस्ता दल गठित किया गया है, जो सहकारी और निजी विक्रेताओं के स्टॉक का नियमित निरीक्षण करेगा। साथ ही जिला स्तर पर भी निरीक्षण जारी रहेगा।

किसानों की सुविधा एवं शिकायत के लिए उप संचालक कृषि कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। किसी भी प्रकार की शिकायत या जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 07752-470814 पर संपर्क किया जा सकता है।

भानु सोनी के नए संगठन पर स्वर्णकार संघ का विरोध, पदाधिकारियों को किया निष्कासित

राजनांदगांव (समय दर्शन)। जिला स्वर्णकार संघ की एक आवश्यक बैठक 6 अप्रैल 2026 को आयोजित हुआ, जिसमें भानु सोनी द्वारा सामांनातर राजनांदगांव जिला सोनार समाज का संगठन बनाये जाने की कड़ी निंदा की गयी। उनका यह कृत्य समाज की एकता खंडित करने वाला है। जिले के सोनार समाज के हितों पर कुठाराघात है। उनके द्वारा सोनार समाज का गठन सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धी व अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए किया जा रहा है। इससे जिले के सभी सोनार बंधुओं को सतर्क रहने की आवश्यकता है। अंत में जिले के सभी सोनार बंधुओं से अपील की है कि भानु सोनी की बात पर न आयें। राजनांदगांव सोनार समाज के नाम पर कोई सदस्यता शुल्क व चंदा न देवें। उनका राजनांदगांव जिला स्वर्णकार संघ से कोई लेना देना नहीं है।

राजनांदगांव जिला स्वर्णकार संघ सन 2011 से रजिस्टार फर्म व सोसायटी रायपुर से पंजीकृत संस्था है। संस्था 16 वर्षों से सोनार समाज के हितों के लिए कार्य कर रही है।

ज्ञात हो कि स्वर्णकार समाज के लिए सामुदायिक भवन कमला कालेज राजनांदगांव के पास निर्माणाधीन है, जो पूर्णता की ओर है।

महेश सोनी, राजू सोनी व प्रणय सोनी राजनांदगांव जिला स्वर्णकार संघ में पदाधिकारी पद पर रहते हुए भानु सोनी द्वारा गठित जिला सोनार समाज के संगठन में पदाधिकारी का पद लिया है, जो संघ के बायोलॉज के नियम 8 (ड) का उल्लंघन है। इसलिए उन्हें संघ के पदों से निष्कासित करने की कार्यवाही का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया है।

उषा पुरुषोत्तम धृतलहरे के नेतृत्व में पिथौरा जनपद की उल्लेखनीय भूमिका

पिथौरा जनपद के 82 ग्राम पंचायत क्षय मुक्त

पिथौरा(समय दर्शन)। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत पिथौरा जनपद पंचायत की 82 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त पंचायतें घोषित करते हुए ग्राम सरपंचों का सम्मान किया गया। जनपद पंचायत के सभागार में आयोजित टीबी मुक्त ग्राम पंचायत सम्मान समारोह की मुख्य अतिथि जनपद अध्यक्ष ऊषा पुरुषोत्तम धृतलहरे थी जबकि अध्यक्षता जनपद उपाध्यक्ष ब्रह्मानंद पटेल ने की। जनपद सीईओ योगेश्वरी बर्मन जनपद सभापति पुरुषोत्तम धृतलहरे और खण्ड चिकित्सा अधिकारी तारा अग्रवाल विशेष रूप से मौजूद रहें।

समारोह में पिथौरा जनपद पंचायत की 60 ग्राम पंचायतों को सिल्वर मेडल एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। जबकि 21 ग्राम पंचायतो को कांस्य पदक एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।जो कि महासमुंद जिले में जनपद पंचायत स्तर पर सर्वाधिक है, कार्यक्रम के दौरान हैंड हेल्ड पोर्टेबल एक्सरे का लोकार्पण किया गया। और धनोरा के सरपंच गिरीश पटेल का डेमो टेस्ट किया गया, टीबी बीमारी की संभावित जांच के लिए यह एक्सरे मशीन अब प्रत्येक ग्राम में आवश्यकता अनुसार उपलब्ध रहेगी। टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में पिथौरा क्षेत्र की उल्लेखनीय उपलब्धि से गदगद जनपद अध्यक्ष ऊषा पुरुषोत्तम धृतलहरे ने सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा की यह जमीनी कार्यकर्ताओं के मेहनत का परिणाम है। कि हम जिले में प्रथम स्थान पर है,उन्होंने इस कार्य में लगे समस्त कर्मचारियों जनप्रतिनिधियों एवं स्वयंसेवकों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। जनपद उपाध्यक्ष ब्रह्मानंद पटेल ने कहा की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एवं पंचायत राज प्रणाली में किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति जनजागरुकता और जनसहभागिता से ही संभव है। पिथोरा ब्लॉक के इस अग्रणी कामयाबी में जमीनी स्तर के कर्मचारियों एवं पंचायत प्रतिनिधियों का पसीना बहा है, जनपद सदस्य पुरुषोत्तम धृतलहरे ने टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में शासन की मंसा अनुसार पिथोरा जनपद स्तर पर चल रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि टीबी मुक्ति की दिशा में पिथौरा की ग्राम पंचायतों को पहले कांस्य पदक और अब सिल्वर मेडल मिला है यह हमें स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रोत्साहित एवं प्रेरित किया है।जो कमियां रह गई है उन्हें दूर किया जाएगा और समय से पहले लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास किया जाएगा। जनपद सीईओ योगेश्वरी बर्मन ने टीबी मुक्त पंचायतों के सम्मान पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि टीबी जैसी संक्रामक बीमारी को लेकर तमाम भ्रांतियां जन मानस में व्याप्त रही है। किंतु अब सरकार के प्रयासों से काफी बदलाव आया है और लोग इसके इलाज के प्रति गंभीर हो रहे है, फिर भी टीबी मुक्ति के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे निश्चय मित्र एवं निश्चय पोषण अभियान जैसे कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार -प्रसार किया जाना चाहिए कार्यक्रम में स्वागत भाषण एवं आभार प्रदर्शन खण्ड चिकित्सा अधिकारी श्रीमती तारा अग्रवाल ने किया तथा कार्यक्रम के उद्देश्यों पर सुपरवाइजर दिनेश पटेल ने प्रकाश डाला कार्यक्रम में जिला प्रोग्राम समन्वयक उत्तम श्रीवास एवं घनश्याम देशमुख, स्वास्थ्य विभाग से आरके अवस्थी, ललेश साहू, तरुण सोनवानी, कमलेश्वर गिरी गोस्वामी, करारोपण अधिकारी सुशील चौधरी, उमेश दीक्षित, सरपंच शशिकला पटेल, रूखमणी सेन, मनोज सिन्हा, पवन साहू, रिबीकांति बरिहा, सुशीला मांझी, सहित बड़ी संख्या में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

संक्षिप्त समाचार

शोभायात्रा के दौरान चाकूबाजी 3 आरोपी गिरफ्तार

रायपुर। हनुमान जयंती के अवसर पर निकली शोभायात्रा के दौरान हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। बिलासपुर के तोरवा थाना क्षेत्र में एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।क्या है पूरा मामला2 अप्रैल को शहर में हनुमान जयंती पर विभिन्न स्थानों पर शोभायात्राएं निकाली जा रही थीं। इसी दौरान चांटीडीह निवासी सन्नी श्रीवास अपने साथी सूरज साहू के साथ पेंडलवार अस्पताल के पास रैली देख रहे थे। इसी बीच दयालबंद निवासी प्रियांशु बोले अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा। साइड हटने को लेकर शुरू हुई कहासुनी जल्द ही गाली-गलौच और मारपीट में बदल गई।आरोप है कि विवाद के दौरान प्रियांशु बोले ने चाकू निकालकर सूरज साहू के पेट में वार कर दिया। घायल युवक को तुरंत सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस की कार्रवाईघटना के बाद तोरवा थाना में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई। आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए छिपते फिर रहे थे, लेकिन पुलिस ने साइबर सेल की मदद से लोकेशन ट्रैक कर 5 अप्रैल को कोतवाली क्षेत्र से तीनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में प्रियांशु बोले (25 वर्ष) ओम बोले (23 वर्ष) राघवेन्द्र राव उर्फ सुरेश (26 वर्ष) शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल किया गया धारदार चाकू भी बरामद किया है। आगे की कार्रवाई तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर दिया गया है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।

पंजीयन पोर्टल के पहले ही गिरदावरी पोर्टल लाक, पी एम आशा योजना का लाभ लेने से किसान वंचित

रायपुर। प्रदेश के रबी दलहन - तिलहन उत्पादक किसानों को निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये पी एम आशा योजना का लाभ लेने से अनेकों किसान वंचित हो गये हैं । इसका कारण किसान पंजीयन पोर्टल के पहले ही गिरदावरी पोर्टल को लाक कर दिया जाना है । किसान पंजीयन हेतु शासन ने अंतिम तिथि बीते 31 मार्च निर्धारित किया था लेकिन इसके पहले ही गिरदावरी पोर्टल विभागीय तालमेल न होने की वजह से बीते 26 मार्च से बंद हो गया है जिसके चलते क्राप सर्वे का इन्द्राज नहीं हो पा रहा । ज्ञातव्य हो कि केंद्र सरकार ने किसानों का आय बढ़ाने , फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने और संकटग्रस्त बिक्री को रोकने के उद्देश्य से किसानों के हित में विभिन्न दलहन - तिलहन फसलों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान जिसे संक्षेप में पी एम आशा योजना बनायी है । प्रदेश के कृषि विभाग ने पहले एकीकृत किसान पोर्टल में ऐसे किसानों के पंजीयन हेतु बीते 01 दिसंबर से बीते 28 फरवरी की तिथि व क्राप सर्वे रिपोर्ट इन्द्राज हेतु गिरदावरी पोर्टल 25 मार्च तक खुला रखने का निर्णय लिया था । इसी बीच कृषि संचालक व विभिन्न जिलाधीशों द्वारा डिजीटल क्राप सर्वे का डाटा तकनीकी त्रुटि के कारण अपडेट नहीं हो पाने के फलस्वरूप संबंधित पोर्टल पर कृषक पंजीयन का ?रकबा/ खसरा का प्रविष्टि नहीं हो पाने की जानकारी देते हुये किसान पंजीयन की समयावधि बढ़ाने की मांग किये जाने पर किसान पंजीयन की तिथि 31 मार्च तक बढ़ा दी गयी पर राजस्व विभाग द्वारा किये जाने वाले क्राप सर्वे (गिरदावरी) का इन्द्राज ?का निर्धारित तिथि विभागीय लापरवाही के चलते पूर्ववत् 25 मार्च ही रह गया । इसकी वजह से खासकर 26 से 31 मार्च तक पंजीयन कराने वाले किसानों का डिजिटल क्राप सर्वे का डाटा इन्द्राज नही हो पाने की जानकारी देते हुये किसान संघर्ष समिति के संयोजक भूपेंद्र शर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय , कृषि मंत्री रामविचार नेताम , प्रमुख सचिव विकासशील व मुख्यमंत्री सचिवालय के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह को मेल से ज्ञापन भेज गिरदावरी पोर्टल आगामी 15 अप्रैल तक रबी उत्पादक किसानों के व्यापक हित में पुन: खुलवाने की मांग की है ।

अलग-अलग सड़क दुर्घटना में शिक्षक समेत दो लोगों की मौत

रायपुर। जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र में हुए दो अलग-अलग सड़क हादसों में एक शिक्षक सहित दो लोगों की मौत हो गई। इन घटनाओं के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है, वहीं सड़क व्यवस्था और रोशनी की कमी पर सवाल उठने लगे हैं। पहली घटना सीताराम चैक के चकचकवा पहाड़ के पास की है। जानकारी के अनुसार, ऐतमा नगर निवासी 25 वर्षीय शिपाल पोर्ते बाइक से किसी काम से निकला था। इसी दौरान सड़क पर पड़े गिट्टी-मिट्टी के ढेर से उसकी बाइक टकरा गई, जिससे वह अनियंत्रित होकर गिर पड़ा। हादसे में युवक के सिर, हाथ और पैर में गंभीर चोटें आईं। राहगीरों की मदद से उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरी घटना बरपाली के पास हुई, जहां पोड़ी उपरोड़ा निवासी शिक्षक जय पांडेय अपनी वैगनआर कार से कहीं जा रहे थे। अंधेरे के कारण उनकी तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। गंभीर रूप से घायल शिक्षक को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटघोरा लाया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर उन्हें कोरबा रेफर किया गया। लेकिन इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई। दोनों घटनाओं के बाद मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों ने सड़क पर पर्याप्त रोशनी और व्यवस्थित निर्माण कार्य की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों को रोका जा सके।

छत्तीसगढ़ के बारिश और आंधी से बदलेगा मौसम, गर्मी से मिली राहत

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश में झुलसाती गर्मी के बीच मौसम ने अचानक करवट ली है। बीती रात राजधानी समेत कई जिलों में हुई बारिश ने लोगों को राहत दी है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट, गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई है, जिससे गर्मी से जूझ रहे लोगों को और राहत मिल सकती है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के एक-दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। नांगुर में 3 सेमी और जगदलपुर में 1 सेमी वर्षा रिकॉर्ड की गई। बारिश के बाद वातावरण में ठंडक घुली, जिससे लोगों ने गर्मी से कुछ राहत महसूस की। मौसम विभाग के अनुसार, बीते 24 घंटों में अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ है। आने वाले 24 घंटों में भी तापमान लगभग स्थिर रहेगा, लेकिन इसके बाद अगले दो दिनों में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस दुर्ग में रहा।

नए वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना एवं नवीन व्यय प्रस्तावों की समीक्षा

आधार बेस उपस्थिति प्रणाली-प्रथम स्थान पर आने वालों की प्रशंसा

- ई-ऑफिस में फाईल बढ़ाते समय सभी नियमों एवं स्पष्ट अभिमत के साथ हो प्रस्तुतिकरण : प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा
- समय पर उपस्थित ना होने वालों पर होगी कार्यवाही

रायपुर/ संवाददाता

आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा की अध्यक्षता में आज नवा रायपुर स्थित आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के सभाकक्ष में गत वर्ष के आय-व्यय एवं नए वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभाग द्वारा कुल बजट का 68 प्रतिशत व्यय किया गया है। प्रमुख सचिव श्री बोरा ने कहा कि सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु जो बजट आंबटित किया जाता है उसका पूर्ण लाभ हितग्राही वर्ग को मिलना चाहिए। इसके लिए वर्ष के प्रारंभ से ही एक कार्ययोजना बनाकर उसपर अमल किया जाए। इस हेतु सभी प्रभारी अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ निर्धारित समय-सीमा में कार्य संपादित करना चाहिए। श्री बोरा ने आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय को 80 प्रतिशत किए जाने का लक्ष्य दिया है। प्रमुख सचिव श्री बोरा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के कुशल नेतृत्व एवं मंत्री श्री रामविचार नेताम के मार्गदर्शन में विभाग प्रगति ओर अग्रसर है। विभागीय योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को देखते हुए भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2025-26 में धरती

आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान हेतु 732 करोड़, 21 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों हेतु 915 करोड़ तथा अनुच्छेद 275 (1) अंतर्गत 170 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है, यह विभाग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो आगामी दो वर्षों में इन सभी कार्यों के सफल क्रियान्वयन से छत्तीसगढ़ के विकास को गति मिलेगी। बैठक में आदिम जाति विकास विभाग के अलावा आदिम जाति अनुंसधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अनुसूचित जाति विकास विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास तथा छ.ग. राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के वित्तीय वर्ष 2025-26 अंतर्गत आय-व्यय की भी समीक्षा की गई। बैठक में संयुक्त सचिव श्री बी.के.राजपूत, श्री अनुपम त्रिवेदी, वित्त नियंत्रक श्री लाजरूस मिंज, अपर संचालक श्री संजय गौड़, श्री आर.एस.भोई, उपायुक्त श्रीमती गायत्री नेताम, श्री प्रज्ञान सेठ, श्री एल.आर.कुर्रे, श्री विश्वनाथ रेडडी, श्रीमती मेनका चंद्राकर, कार्यपालन अभियंता श्री त्रिदीप चक्रवर्ती सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। प्रमुख सचिव श्री बोरा ने बैठक में आधार फेस उपस्थिति प्रणाली एवं ई-ऑफिस व्यवस्था की भी समीक्षा की। आधार बेस उपस्थिति प्रणाली में विभाग में सर्वाधिक उपस्थिति वाले अधिकारी-कर्मचारियों की प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने कहा कि समय पर नहीं आने वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रमुख सचिव श्री बोरा ने बैठक में ई-ऑफिस की भी समीक्षा करते हुए कहा कि ई-ऑफिस व्यवस्था लागू होने से प्रशासन में पारदर्शिता एवं कसावट आई है। साथ ही व्यवस्था सुदृढ़ करने में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रही है। उन्होंने कहा कि अब ई-ऑफिस में फाईल आने के बाद से बहुत ही तीव्र गति से कार्य संचालन संभव हुआ है। अधिकारी फाईल बढ़ाते समय सभी नियमों एवं स्पष्ट अभिमत के साथ ही फाईल को प्रस्तुत करें, ताकि उस पर अंतिम रूप से निर्णय लिया जा सके।

बिजली बिल समाधान योजना से धमतरी के हजारों परिवारों को मिली आर्थिक आजादी

रायपुर/ संवाददाता

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य शासन द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना-2026 प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। धमतरी जिले में इस योजना का व्यापक असर देखने को मिल रहा है, जहाँ हजारों उपभोक्ता वर्षों पुराने बिजली बिल के बोझ से मुक्त होकर विकास की मुख्यधारा में लौट रहे हैं। धमतरी निवासी श्री बी. एस. विशाल के परिवार के लिए बिजली का बकाया बिल एक मानसिक तनाव बन चुका था। सीमित आय और पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते बिल की राशि बढ़ती गई, जिससे बिजली कटने का डर हमेशा बना रहता था। जब शासन की समाधान योजना की घोषणा हुई, तो उनके पुत्र डेनियल विशाल ने विभागीय शिविर में संपर्क किया। मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना-2026 की प्रक्रिया इतनी सरल थी कि उन्हें जल्द ही योजना का लाभ मिला। डेनियल ने बताया कि बकाया मूल राशि में भारी छूट और सरचार्ज की शत-प्रतिशत माफी ने हमारे परिवार को नई शुरुआत करने का मौका दिया है। अब हम नियमित रूप से बिल चुकाने की स्थिति में हैं। यह योजना हम जैसे आम लोगों के लिए मुख्यमंत्री का बड़ा उपहार है। विद्युत विभाग द्वारा जारी ताजा आँकड़ों के अनुसार, जिले में योजना को लेकर जबरदस्त उत्साह है। इस योजना के लिए अब तक 4,652 पात्र उपभोक्ताओं की

पहचान की जा चुकी है। इसमें से 4,115 उपभोक्ताओं ने ऑफलाइन माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। आवेदन के बाद 537 परिवारों को पहले ही बकाया मुक्त कर प्रत्यक्ष लाभ दिया जा चुका है। योजना की रूपरेखा इस तरह तैयार की गई है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक इसका फायदा पहुँचे। गरीबी रेखा से नीचे के उपभोक्ता को बकाया मूल राशि पर अधिकतम 75 प्रतिशत तक की भारी छूट दिया जा रहा है। इसी तरह घरेलू एवं कृषि उपभोक्ता को मूल बकाया राशि में 50 प्रतिशत तक की राहत दिया जा रहा है। सभी पात्र श्रेणियों के लिए लेट पेमेंट सरचार्ज (अधिभार) को 100 प्रतिशत माफ कर दिया गया है। उपभोक्ता को केवल 10 प्रतिशत प्रारंभिक राशि जमा करनी होगी, जिसके बाद शेष राशि को वह अपनी सुविधा अनुसार निर्धारित किस्तों में जमा कर सकता है। यह योजना 12 मार्च 2026 से शुरू होकर 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेगी। विद्युत विभाग द्वारा गांव-गांव और वार्डों में विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति जानकारी के अभाव में छूट न जाए।

जल जीवन मिशन से ढिटोरी की महिलाओं के जीवन में आई नई मुस्कान

- घर पर ही स्वच्छ पानी उपलब्ध होने से महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है और उनके भीतर एक नया आत्मविश्वास जागृत हुआ

रायपुर/ संवाददाता

आदिवासी बहुल कोरबा जिले के करतला विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत बुढियापाली का आश्रित ग्राम ढिटोरी, जो जिला मुख्यालय से लगभग 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, आज विकास की एक नई इबारत लिख रहा है। लगभग 763 की जनसंख्या वाले इस गाँव में पहले स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती थी, जिससे विशेषकर महिलाओं को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। गाँव की 38 वर्षीय जोगिनी बाई उन दिनों को याद करते हुए बताती हैं कि उन्हें पानी लाने के लिए घर से काफी दूर जाना पड़ता था। गर्मी हो या बारिश, हर मौसम में साफ पानी का इंतजाम करना एक संघर्ष जैसा था, जिससे न केवल समय की बर्बादी होती थी बल्कि शारीरिक श्रम भी अधिक करना पड़ता था। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी 'हर घर जल' पहल और जल जीवन मिशन के माध्यम से ढिटोरी की यह तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। मिशन के तहत ग्राम ढिटोरी के सभी 176 घरों को नल कनेक्शन से जोड़ दिया गया है, जिससे अब ग्रामीणों को सुबह और शाम उनके घर पर ही पाइपलाइन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल प्राप्त हो रहा है। इस योजना के क्रियान्वयन से ग्रामीण महिलाओं को पानी ढोने के पुराने और कठिन काम से बड़ी राहत मिली है, जिससे उनके समय और श्रम की बचत हो रही है। जल जीवन मिशन ने न केवल पेयजल की समस्या का निदान किया है, बल्कि इसने ग्रामीण समाज की महिलाओं के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव भी लाया है। घर पर ही स्वच्छ पानी उपलब्ध होने से महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है और उनके भीतर एक नया आत्मविश्वास जागृत हुआ है। आज ढिटोरी की महिलाएं घर के साथ-साथ सामाजिक भागीदारी और आत्मनिर्भरता की ओर भी कदम बढ़ा रही हैं। पानी की उपलब्धता ने गाँव में खुशहाली का संचार किया है और जोगिनी बाई जैसी अनेक महिलाओं के जीवन को सम्मान और गरिमा के साथ सहज बना दिया है।

महतारी वंदन योजना से प्रदेश की महिलाओं को मिला आर्थिक संबल

- घरेलू खर्चों और आवश्यक वस्तुओं की खरीदी में सुविधा मिल रही

रायपुर/ संवाददाता

राज्य सरकार द्वारा संचालित महतारी वंदन योजना प्रदेशभर की महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम बनकर उभर रही है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की जा रही है, जिससे वे अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में आत्मनिर्भर बन रही हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों से इस योजना के

सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के ग्राम परसाभदेर की निवासी श्रीमती चारबाई निषाद भी इस योजना से लाभान्वित महिलाओं में शामिल हैं। सीमित आय वाले परिवार से होने के कारण उनके लिए घर का खर्च चलाना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन अब महतारी वंदन योजना से मिलने वाली राशि उनके परिवार के लिए सहारा बन गई है। श्रीमती चारबाई बताती हैं कि इस आर्थिक सहयोग से उन्हें घरेलू खर्चों और आवश्यक वस्तुओं की खरीदी में सुविधा मिल रही है। अब उन्हें छोटी-छोटी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। यह योजना न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर रही है, बल्कि उनके आत्मविश्वास में भी वृद्धि कर रही है। महतारी वंदन योजना के माध्यम से राज्य सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। योजना का लाभ उठाकर प्रदेश की लाखों महिलाएं अपने परिवार की आर्थिक मजबूती में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

जूस की बर्फ से निकला मरा मेंढक, चैपाटी में मचा हड़कंप

रायपुर। शहर के घंटाघर चैपाटी क्षेत्र में शुक्रवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक जूस दुकान में इस्तेमाल की जा रही बर्फ के अंदर से मृत मेंढक निकल आया। इस घटना से मौके पर मौजूद लोग हैरान रह गए और क्षेत्र में स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जूस बनाते समय जैसे ही बर्फ तोड़ी गई, उसमें मरा हुआ मेंढक दिखाई दिया। यह दृश्य देखकर ग्राहकों में दहशत फैल गई और कुछ ही देर में बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही चैपाटी समिति के अध्यक्ष ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की और संबंधित दुकान से खाद्य सामग्री लेने से बचने को कहा। स्थानीय लोगों ने इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए खाद्य विभाग और नगर प्रशासन पर सवाल उठाए हैं।

कौशल प्रशिक्षण से बन रहे हुनरमंद

पुनर्वासित व्यक्तियों को मिल रही आत्मनिर्भरता की नई राह

रायपुर/ संवाददाता

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य शासन की पुनर्वास नीति के तहत कोण्डागांव जिले में पुनर्वासित व्यक्तियों को मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रभावी पहल की जा रही है। जिले में स्थापित पुनर्वास केन्द्र आज उन लोगों के लिए आशा और नवजीवन का केन्द्र बन चुका है, जिन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़कर शांति और विकास की राह अपनाई है। जिले में वर्तमान में 48 पुनर्वासित व्यक्ति हैं, जिन्हें शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। पुनर्वासित व्यक्तियों को उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिनमें असिस्टेंट शटरिंग कारपेंटर, गार्डनर, वाहन मेकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, सिलाई-कढ़ाई जैसे रोजगारोन्मुखी कौशल शामिल हैं। इन प्रशिक्षणों का उद्देश्य उन्हें हुनरमंद बनाते हुए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करना है।प्रथम चरण में 38 व्यक्तियों को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित किया जा चुका है। वहीं वर्तमान में लाईवलीहुड कॉलेज में 10 पुनर्वासित व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें 7 व्यक्तियों को सिलाई एवं 3 को इलेक्ट्रिशियन का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण न केवल तकनीकी दक्षता प्रदान कर रहा है, बल्कि उनमें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान भी बढ़ा रहा है। मड़हो बाई कोर्राम और हाड़ोबाई सोडी बताती हैं कि पुनर्वास केन्द्र में रहते हुए वे सिलाई-कढ़ाई का कार्य सीख रही हैं। उनका कहना है कि प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद वे अपने गांव लौटकर स्वयं का रोजगार शुरू करेंगी और आत्मनिर्भर होकर जीवनयापन करेंगी। इसी प्रकार मोहन कोर्राम, जो वर्ष 2004 में माओवादी संगठन से जुड़े थे, अब शासन की पुनर्वास नीति का लाभ लेकर सिलाई का प्रशिक्षण प्राप्त

कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे इस कौशल के माध्यम से अपने गांव में स्वरोजगार स्थापित कर शांतिपूर्ण जीवन यापन करना चाहते हैं। राज्य शासन द्वारा पुनर्वासित व्यक्तियों को प्रशिक्षण के साथ-साथ आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वरोजगार हेतु विभिन्न योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया जा रहा है और उन्हें समाज की मुख्यधारा में सम्मानपूर्वक पुनर्स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। शासन की पुनर्वास नीति और जनकल्याणकारी योजनाएं मिलकर पुनर्वासित लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रही है।

नक्सलवाद का अंधेरा छोड़ शर्मिला ने थामी स्वावलंबन की सुई

बस्तर संभाग के नक्सल मुक्त घोषित होने के बाद अब हिंसा का रास्ता छोड़ मुख्यधारा में लौटने वाले युवाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखने लगा है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल बीजापुर की शर्मिला पोयामी बनकर उभरी हैं, जिन्होंने कभी हाथों में बंदूक थामी थी, लेकिन आज वे लाइवलीहुड कॉलेज में सुई-धागे से अपने और अपने परिवार के भविष्य के सपने बुन रही हैं। बीजापुर जिले के भैरमगढ़ ब्लॉक की रहने वाली 19 वर्षीय शर्मिला कभी भैरमगढ़ एरिया कमेटी की सक्रिय सदस्य थीं। गुरिल्ला युद्ध और हथियारों का प्रशिक्षण लेने वाली शर्मिला को जल्द ही अहसास हो गया कि प्रगति का मार्ग बंदूक से नहीं, बल्कि शांति और शिक्षा से निकलता है। इसी संकल्प के साथ उन्होंने 07 फरवरी 2026 को आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का निर्णय लिया। राज्य शासन की पुनर्वास नीति के तहत शर्मिला को दंतेवाड़ा के लाइवलीहुड कॉलेज में प्रवेश दिलाया गया। बीते 45 दिनों से वे यहाँ सिलाई का गहन प्रशिक्षण ले रही हैं।

संपादकीय

सोशल मीडिया की लत

युवा या किसी उम्र वर्ग के व्यक्ति को सोशल मीडिया की लत क्यों लगती है? कुछ अध्ययनों के मुताबिक युवा अपने खालीपन की भरपाई सोशल मीडिया से करते हैं, जहां अल्पकालिक उत्तेजना और निरर्थक सूचना देने वाले स्रोतों की भी भरमार है। भारत सहित तमाम देशों में सोशल मीडिया युवाओं के बीच खुशी घटा रहा है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट- 2026 के अनुसार कुल मिलाकर युवाओं की खुशी पर सोशल मीडिया का असर नकारात्मक है। बहरहाल, उभरे रुझानों के लिए महज सोशल मीडिया को दोष देना शायद ठीक ना हो। खुद इसी रिपोर्ट के मुताबिक जो युवा सोशल मीडिया का रोजाना एक घंटे से कम इस्तेमाल करते हैं, वे इससे खुशी और संतुष्टि प्राप्त करते हैं। संभवत: इसलिए कि इस दौरान वे अपने दोस्त- रिश्तेदारों से संपर्क करते हैं और अपने लिए जरूरी सूचनाएं या मनोरंजन हासिल कर लेते हैं। उसके बाद वास्तविक समाज या इनसानी दायरे से जुड़ने के लिए उनके पास पर्याप्त समय रहता है, जहां उन्हें बेहतर अहसास हासिल होता है। तो प्रश्न है कि आखिर युवा या किसी उम्र वर्ग के व्यक्ति को सोशल मीडिया की लत क्यों लगती है? क्या यह परिवार में बढ़ते एकाकीपन एवं समाज में घटती सामूहिकता का परिणाम है? कुछ अध्ययनों के मुताबिक उपरोक्त कारणों से युवा खालीपन का शिकार होते हैं, जिसकी भरपाई वे सोशल मीडिया से करते हैं, जहां अल्पकालिक उत्तेजना, क्षणिक मनोरंजन, और निरर्थक सूचना देने वाले स्रोतों की भी भरमार है। हैप्पीनेस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि युवाओं के सोशल मीडिया उपयोग पर नियंत्रण की दिशा में नीति-निर्माताओं को कदम उठाने चाहिए। दरअसल, हाल में कई देशों और भारत के कुछ राज्यों में ऐसे कदम उठाए भी गए हैं। मगर उनकी सफलता संदिग्ध है, क्योंकि बच्चों और युवाओं के सामने समय के बेहतर और आनंददायक उपयोग का विकल्प दिए बिना जबरन सोशल मीडिया से उन्हें अलग करना अलग तरह की मुश्किलों को जन्म दे सकता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट विभिन्न देशों के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, सामाजिक सहायता प्रणालियों की उपलब्धता, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, जीवन संबंधी फैसले लेने की स्वतंत्रता की स्थिति, समाज में उदारता अथवा दानशीलता की भावना, और भ्रष्टाचार के संबंध में जन-धारणा की कसौटियों पर तैयारी की जाती है। अगर इन बिंदुओं पर समाज में अपेक्षित प्रगति हो, तो संभव है कि फिर सोशल मीडिया की लत की समस्या से भी समाज बचा रह सकेगा।

भारतीय शासन व्यवस्था की पटकथा फिर से लिख रहा है मिशन कर्मयोगी

डॉ जितेंद्र सिंह

कल्पना करें कि राजस्थान के दूरदराज के किसी कोने में जिला कलेक्टर को एक ऐसी महत्वाकांक्षी कल्याण योजना की जिम्मेदारी सौंपी जाती है जिसके बारे में उसकी जानकारी बहुत कम है। एक दशक पहले उसे जानकारी के लिए कहीं धूल खा रही किसी नियमावली का सहारा लेना होता। या फिर वह अपने किसी वरिष्ठ सहयोगी की तीन बैठकों और लंच के बाद खाली होने का इंतजार करता। उसकी उम्मीद उस प्रशिक्षण कार्यक्रम पर भी टिकी हो सकती थी जो शायद एक या दो साल में कभी आता। लेकिन आज वह अपने फोन के जरिए आईगॉट (इंटिग्रेटेड गर्वनमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म) पर लॉग ऑन करता है। उसे मिनटों में ही अपनी जरूरत के अनुरूप एक सुव्यवस्थित कार्यकुशलता आधारित पाठ्यक्रम मिल जाता है। वह शाम तक सूचनाओं और आत्मविश्वास से लैस होकर योजना के लाभार्थियों की पहली बैठक की अध्यक्षता कर रहा होता है। यह बदलाव देखने में छोटा लग सकता है मगर हकीकत में किसी क्रांति से कम नहीं है। चमक-दमक से दूर धैर्य के साथ पांच साल पहले शुरू किया गया मिशन कर्मयोगी एक क्रांति ला रहा है। यह नए भारत के लिए एक नई तरह के प्रशासनिक अधिकारी तैयार करने के उद्देश्य से चुपचाप काम कर रहा है। इसके महत्व को समझने के लिए हमें पहले संदर्भ को जानना होगा। 2047 तक विकसित भारत के प्रधानमंत्री के निर्धारित लक्ष्य तक यूं ही नहीं पहुंचा जा सकता। इस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें भारत गणतंत्र को चलाने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों के जरिए सावधानी से एक-एक कदम आगे बढ़ना होगा। इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण पूंजी, प्रौद्योगिकी या नीति नहीं है। सबसे ज्यादा अहमियत उन लगभग 3.5 करोड़ प्रशिक्षित, उत्साही और नागरिक केंद्रित सरकारी कर्मियों की क्षमता की है जो हर सुबह उठ कर भारतीय शासन को संचालित करते हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ज्यादातर समय क्षमता निर्माण का मॉडल सांयोगिक रहा है। किसी नौजवान अधिकारी को सेवा की शुरुआत के समय औपचारिक प्रशिक्षण दिया जाता था। फिर करियर के बीच में यदा-कदा उसे कुछ पाठ्यक्रमों में हिस्सा लेने का अवसर मिल सकता था। बाकी, उसे काम करते हुए और दूसरों को देख कर ही सीखना होता था। एक स्थिर और धीमी गति से आगे बढ़ते विश्व में यह काफी था। लेकिन कृत्रिम मेधा, जलवायु अवरोध, जनसांख्यिकीय दबाव और जबर्दस्त प्रौद्योगिकीय परिवर्तन के युग में यह सरासर नाकाफी है। प्रशासन के सामने चुनौतियां जिस रफ्तार से आती हैं उसके सामने प्रशिक्षण की पुरानी प्रणालियों की गति कहीं नहीं टिकती। मिशन कर्मयोगी को इसी बेमेल स्थिति के समाधान के रूप में की गई थी। 2021 में शुरू किया गया यह मिशन—जिसे उसी वर्ष अप्रैल में स्थापित क्षमता निर्माण आयोग द्वारा संस्थागत रूप से संचालित किया गया, एक सचमुच महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ा। भारतीय सिविल सेवाओं की सीखने की संस्कृति को, समय-समय पर होने वाली और केवल नियमों के पालन तक सीमित प्रक्रिया से बदलकर, एक निरंतर चलने वाली, भूमिका-आधारित और स्वयं-निर्देशित विकास यात्रा में रूपांतरित करना इसका मकसद है। जैसा कि आयोग इसका वर्णन करता है, यह बदलाव कर्मचारी—यानी नियमों का पालन करने वाले एक पदाधिकारी से कर्मयोगी बनने की ओर है- एक ऐसा लोक सेवक जो किसी उद्देश्य, सेवा-भाव और उत्कृष्टता से प्रेरित हो। पाँच वर्षों के बाद, ये आंकड़े अत्यंत शिक्षाप्रद हैं। 'आईगॉट' (इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग) प्लेटफॉर्म पर अब 1.5 करोड़ से अधिक सरकारी अधिकारी सक्रिय शिक्षार्थी के रूप में जुड़े हैं।

बागी सिपाहियों को सबक सिखाने के मूड में कांग्रेस

उमेश चतुर्वेदी

पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आती जा रही है, चुनावी घमासान बढ़ता जा रहा है। देश की सबसे पुरानी पार्टी का दांव चूंकि दो राज्यों में ही सबसे ज्यादा है, इसलिए उसका सारा ध्यान इन्हीं दो राज्यों पर है। असम और केरल के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की स्थिति अलग-अलग है। इसलिए दोनों ही राज्यों में उसकी चुनौतियां अलग हैं, इसलिए उसकी लड़ाई के रूप और तरीके अलग-अलग हैं। हरियाली और समुद्री किनारे के चलते केरल को खूबसूरत राज्यों में शुमार किया जाता है। इस खूबसूरती की ही वजह से केरल को 'भगवान का देश' कहा जाता है। बारह साल से केंद्रीय सत्ता से दूर कांग्रेस को उम्मीद भगवान के इसी देश से ही ज्यादा है। पिछले लोकसभा चुनावों में जिस तरह इस राज्य से उसे समर्थन मिला था, उसकी वजह से उसकी उम्मीदों का परवान चढ़ना स्वाभाविक है। लेकिन यहां उसकी चुनौती भगवान को न मानने वाली विचारधारा से है। केरल की सत्ता पर काबिज जिस वाममोर्चा से विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का मुकाबला है, राष्ट्रीय स्तर पर मोदी के खिलाफ बने विपक्षी मोर्चे में कांग्रेस उसी वाममोर्चे के साथ है। स्थानीय स्तर पर विरोध और राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग का विरोधाभास अगर सर्वाधिक शिक्षित राज्य में भारी पड़ सकता है। हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में राजधानी तिरूअनंतपुरम् में जीत हासिल कर चुकी बीजेपी इस विरोधाभास को खूब उछाल रही है। वैसे तो बीजेपी का दावा है कि इस बार भगवान के देश में भगवा ध्वज फहरने जा रहा है, हालांकि अब तक चुनावी अभियान से साफ है कि बीजेपी को वैसी सफलता मिलती नजर नहीं आ रही। लेकिन बीजेपी का मौजूदा जीन आखिरी दम तक हार नहीं मानने का है। इसलिए पार्टी की कोशिश सीपीएम की अगुआई वाले वाममोर्चे और कांग्रेस की अगुआई वाले संयुक्त मोर्चे के विरोधाभास को उजागर करने पर है। पार्टी को लगता है कि देश के इस सर्वाधिक साक्षर राज्य में अगर जनता ने इस विरोधाभास को समझ लिया तो राज्य के चुनावी नतीजे 2017 के उत्तर प्रदेश के परिणामों की तरह आश्चर्यजनक रूप से अपने पक्ष में किए जा सकते है। 2017 में किसने सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत हासिल करेगी। इसी कोशिश के तहत अमित शाह केरल की करीब 19 प्रतिशत जनसंख्या वाले ईसाई समुदाय से लगातार संपर्क कर रहे हैं। साल 2011 की जनगणना के अनुसार, केरल के कुल 3.34 करोड़ निवासियों में से लगभग 61.41 लाख ईसाई हैं, जो मुख्य रूप से मध्य केरल में केंद्रित हैं। पारंपरिक रूप से केरल में यह समुदाय कांग्रेस का सहयोग करता रहा है, लेकिन बीजेपी की कोशिश इस समुदाय को कांग्रेस से तोड़ने की रही है। हालिया अतीत के कुछ चुनावों में यह समुदाय बीजेपी के साथ खड़ा होता नजर आया है। इसकी वजह यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित लव जेहाद का शिकार केरल में यह समुदाय भी होता रहा है। इससे स्थानीय स्तर पर इस समुदाय में भी कुछ वैसा ही गुस्सा है, जैसा उत्तर भारत में हिंदू समाज में ऐसा नजर आता है। कांग्रेस का संकट है कि वह वाममोर्चा का विरोध और समर्थन की उलटबांसी की सटीक काट नहीं खोज पा रही है। इस वजह से राज्य का चुनावी मुकाबला लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। वैसे बीजेपी जिस तरह की कोशिश करती नजर आ रही है, उससे सबसे ज्यादा संकट में कांग्रेस की संभावनाएँ ही नजर आ रही है। ऐसा लगता है कि बीजेपी की रणनीति कांग्रेस को इस राज्य की सत्ता से दूर रखने की ही है।

पूर्वोत्तर भारत के प्रमुख राज्य असम की जहां तक बात है, तो वहां मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में ही है। कांग्रेस की चिढ़ यह है कि बीजेपी जिस हिमंत विस्वसरमा के चेहरे पर चुनावी मैदान में है, वह कभी कांग्रेस का ही चेहरा होते थे। कांग्रेस अपने इस पूर्व नेता को इस बार हर हाल में सबक सिखाने के मूड में नजर आ रही है। जिस तरह उनकी पत्नी रिंकी भुइयां सरमा के पास तीन-तीन पासपोर्ट हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का आरोप है कि रिन्की भुइयां सरमा के पास संयुक्त अरब अमीरता, एंटीगुआ और बारबुडा एवं मिस्त्र का पासपोर्ट है। कांग्रेस ने इसके समर्थन के कुछ दस्तावेज़ों की कॉपी भी दिखाई है। हालांकि हिमंत विस्वसरमा का कहना है कि कांग्रेस हताशा में है और उनकी ओर से कांग्रेस के नेताओं पर मानहानि का केस दायर करने की भी बात कही जा रही है। कांग्रेस एक तरह से अपने इस पुराने सिपाही को भ्रष्टतम साबित करने की कोशिश में है। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि हिमंत के पास अमेरिका में भी कंपनी है, जिसमें बावन हजार करोड़ रूपए जमा हैं। कांग्रेस का यह आरोप राहुल गांधी के आरोपों का विस्तार ही लगता है। राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले उन्होंने अपने पुराने सहयोगी को देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताया था। राहुल गांधी उन्हें सत्ता में वापसी के बाद जेल भेजने की बात कहते रहे हैं। कांग्रेस की इन आरोपों के जरिए कोशिश सिर्फ हिमंत को ही सवालों के घेरे में रखना नहीं है, बल्कि बीजेपी को भी भ्रष्टाचार बताने की भी है। वैसे हिमंत भी राहुल गांधी की आलोचना करते रहे हैं। अपने कांग्रेस छोड़ने की वजह वे राहुल गांधी को ही बताते रहे हैं। दोनों के रिश्तों के संदर्भ में मौजूदा आरोपों को देखें तो यह निजी खुन्नस का भी मामला लगता है। हिमंत इन आरोपों को निजी खुन्नस बताने और असम के लोगों को समझाने की कोशिश में लगे हैं। अगर वे इसमें कामयाब रहे तो असम में कांग्रेस की चुनावी संभावना दूर होगी। अगर ऐसा हुआ तो फिर कांग्रेस के लिए उत्तर पूर्व में अपनी मौजूदगी बनाए रखना दूर की कौड़ी हो जाएगा। इसका कारण यह है कि हिमंत पूर्वोत्तर भारत में बीजेपी का चेहरा और संकट मोचक बन चुके हैं। अगर कांग्रेस की कोशिशें कामयाब रहीं तो पूर्वोत्तर में बीजेपी की राह कठिन हो जाएगी। हिमंत की हार उसकी चुनावी संभावनाओं पर बड़ा प्रश्नचिन्ह बनकर उभरेगी। असम पर काबू पाने के लिए कांग्रेस ने अपने हरावल दस्ते के हर हथियार मैदान में उतार दिए हैं। कांग्रेस की कोशिशों को पलीता उसकी प्रेस कांफ्रेंस में ही लगता दिखा, जब राष्ट्रीय मीडिया के एक पत्रकार ने उस कंपनी की वेबसाइट खोलकर उसकी स्थापना के तथ्य कांग्रेस प्रवक्ता के सामने पेश करने शुरू कर दिए, जो कांग्रेस के दावे के ठीक उलट नजर आ रहे थे। इसका माकूल और संतोषजनक जवाब कांग्रेस प्रवक्ता नहीं दे पाए। असम से सटे पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। वहां तो वह लड़ती भी नहीं दिख रही। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कभी कांग्रेस की सिपाही रहीं। केरल की तरह पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस विरोधाभास से जूझ रही है। राष्ट्रीय स्तर पर वह ममता के साथ है, लेकिन राज्य में उसकी पूरी कोशिश ममता को हिमंत की तरह सबक सिखाने की ही लग रही है। दरअसल राज्य में कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है। हालांकि 2023 में मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले की सगरदीघी सीट के उपचुनाव में कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस को हराकर विधानसभा में अपना खाता खोलने में सफल रही थी। मुस्लिम बहुल विधानसभा में कांग्रेस की जीत से ममता की नींद उड़ गई थी। राज्य के करीब पैंतीस फीसद मुस्लिम वोट बैंक में सेंध का डर उन्हें सताने लगा। इसके लिए उन्होंने ऑपरेशन सगरदीघी शुरू किया और यहां से जीते कांग्रेसी विधायक बायरन विश्वास को तृणमूल कांग्रेस में शामिल करा दिया। कांग्रेस ने इसे विश्वासघात माना और लगता ऐसा है कि वह ममता को इन चुनावों में सबक सिखाने की कोशिश कर रही है। वैसे पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान राज्य की ग्यारह मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटों पर उसके प्रत्याशी पहले नंबर पर रहे थे। इसलिए कांग्रेस यह मानकर चल रही है कि विधानसभा चुनावों में उसे मुस्लिम वोटरों का साथ मिल सकता है। उसकी पूरी रणनीति इसी लिहाज से आगे बढ़ रही है।

साफ है कि इस बार के चुनावों में कांग्रेस जहां अपने पुराने सिपाहियों को सिखाने की कोशिश में है, वहीं खुद की संभावनाएं बेहतर करने का भी प्रयास कर रही है।

तेल की तलवार और कूटनीति की ढाल: पश्चिम एशिया संकट में भारत की अग्निपरीक्षा

योगेश कुमार गोयल

दशकों पहले युद्ध केवल सीमाओं पर जमीन के टुकड़ों के लिए लड़े जाते थे लेकिन 2026 का यह दौर गवाह है कि आधुनिक युद्ध 'संप्रभुता' से ज्यादा 'संसाधनों' का है। युद्ध की गोलियां, मिसाइलें अब ऊर्जा की पाइपलाइनों और तेल के टैंकरों पर चलती है। पश्चिम एशिया में ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच छिड़ा यह त्रिकोणीय संघर्ष भी महज जमीन का विवाद नहीं है बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा 'ऊर्जा आपूर्ति' पर नियंत्रण की जंग है। भारत के लिए यह संकट केवल पैट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों तक सीमित नहीं है बल्कि यह एक ऐसी राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती है, जिसने देश के सामने एक अदृश्य 'ऊर्जा लॉकडाउन' का खतरा पैदा कर दिया है। जब संसद में प्रधानमंत्री ने इस संकट की तुलना 'कोरोना काल' की विभीषिका से की तो उनका आशय घर में बंद होने से नहीं बल्कि उस वैश्विक अनिश्चितता से था, जो किसी भी क्षण भारत की विकास दर के पहियों को जाम कर सकती है। यदि 'स्ट्रेट ऑफहोर्मुज' पर ताला लगता है तो भारत की रगों में दौड़ने वाला 60 प्रतिशत तेल और एलएनजी का प्रवाह थम जाएगा, जो देश को एक भयावह 'ऊर्जा लॉकडाउन' की ओर धकेल सकता है।

होर्मुज की घेराबंदी- विश्व मानचित्र पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज वह संकरा जलमार्ग है, जिससे दुनिया का लगभग 20 प्रतिशत कच्चा तेल और भारी मात्रा में एलएनजी गुजरती है। ईरान द्वारा इस जलमार्ग को प्रभावित करने का अर्थ है, वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की गर्दन दबाना। फरवरी 2026 के अंत से शुरू हुए इस युद्ध ने मात्र पांच हफ्तों में कच्चे तेल की कीमतों को 85 डॉलर से 110 डॉलर के पार पहुंचा दिया है। भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का 40 प्रतिशत अकेले कतर से पूरा करता है। कतर के रास लाफान एलएनजी प्लांट पर हुए हमलों ने न केवल उत्पादन घटाया है बल्कि भारत के घरेलू चूल्हों तक पहुंचने वाली गैस की कीमतों में आग लगा दी है। युद्ध शुरु होने के बाद से अब तक कच्चे तेल की कीमतें 85 डॉलर से उछलकर 110 डॉलर प्रति बैरल को छू रही हैं। भारत के लिए गणित सीधा और क्रूर है, कच्चे तेल में 10 डॉलर की हर बढ़ोतरी हमारे चालू खाता घाटे में लगभग 12-15 अरब डॉलर की वृद्धि करती है। यह स्थिति हमें दो टूक शब्दों में चेतावनी दे रही है कि पराई बैसाखियों पर टिकी ऊर्जा सुरक्षा कभी भी धराशायी हो सकती है।

सामरिक पैट्रोलियम भंडार: क्या पर्याप्त है चंद दिनों की सुरक्षा?- ऊर्जा सुरक्षा के मोर्चे पर भारत की सबसे बड़ी कमजोरी उसका सीमित सामरिक पैट्रोलियम भंडार है। दुनिया के विकसित देश जैसे अमेरिका, जापान और चीन अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए 90 दिनों का 'स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व' रखते हैं, वहीं भारत की स्थिति चिंताजनक है। वर्तमान में हमारे पास विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पाडुर में कुल 53.3 लाख टन का भंडार है, जो मुश्किल से 9 दिन की आपूर्ति कर सकता है। हालांकि दूसरे चरण में चंडीखोल और बीकानेर जैसे स्थानों पर भंडार क्षमता बढ़ाकर इसे 60-65 दिनों तक ले जाने की योजना है लेकिन इसकी गति 'युद्धस्तर' पर नहीं है। हमारे मौजूदा भंडार का करीब 36 प्रतिशत हिस्सा खाली पड़ा है। एक तरफ हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का स्वप्न देख रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी ऊर्जा की 'लाइफलाइन' केवल कुछ दिनों के स्टॉक पर टिकी है। यदि आज हमारे पास 90 दिनों का सुरक्षित भंडार होता तो भारत को अपनी विदेश नीति में तटस्थता का नाटक नहीं करना पड़ता बल्कि वह एक सशक्त वैश्विक खिलाड़ी की तरह अपना पक्ष रख सकता था। यदि होर्मुज जलडमरूमध्य 30 दिनों के लिए बंद हो जाता है और भारत के लिए आपूर्ति बाधित होती है तो भारत की अर्थव्यवस्था 'वेंटिलेटर' पर आ जाएगी। इसलिए चंडीखोल और बीकानेर में प्रस्तावित दूसरे चरण के भंडारों का निर्माण युद्धस्तर पर होना अब विकल्प नहीं, अनिवार्यता है।

कूटनीतिक विवशता और स्वतंत्र विदेश नीति का संकट- भारत की रणनीतिक स्वायत्तता आज तेल की निर्भरता के कारण परीक्षा की घड़ी में है। तेल की निर्भरता केवल आर्थिक बोझ नहीं बल्कि कूटनीतिक बेड़ियां भी है। भारत को अपने पुराने और रणनीतिक मित्र ईरान का साथ छोड़कर इजरायल और अमेरिकी समर्थित खाड़ी देशों के पाले में खड़े होने पर मजबूर होना पड़ा है। यह बदलाव केवल नीतिगत नहीं बल्कि विवशतापूर्ण है। खाड़ी देशों में रहने वाले 90 लाख भारतीयों की सुरक्षा और वहां से आने वाला 'रेमिटेंस' भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसलिए खाड़ी देशों में रहने वाले 90 लाख भारतीय प्रवासियों के हितों और तेल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ही भारत को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति से समझौता करना पड़ रहा है। जब तक हम ऊर्जा के लिए आयात पर 85 प्रतिशत निर्भर रहेंगे, तब तक हमारी विदेश नीति की चाबी विदेशी राजधानियों के हाथों में रहेगी और वाशिंगटन या तेहरान में होने वाली हर हलचल नई दिल्ली के माथे पर चिंता की लकीरें खींचती रहेगी। यह युद्ध हमें सिखाता है कि सच्ची संप्रभुता केवल सीमाओं की रक्षा में नहीं बल्कि ऊर्जा की आत्मनिर्भरता में निहित है।

अफवाहों का बाजार और सरकारी डैमेज कंट्रोल- युद्ध के बीच भारत में लॉकडाउन की अफवाहों ने पैनिक पैदा किया है। हालांकि, तीन मंत्रियों निर्मला सीतारमण, किरेन रिजिजू और हरदीप पुरी ने स्पष्ट किया कि देश सुरक्षित है। सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि भारत के पास तेल और गैस की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विविधीकृत स्रोत हैं और पैनिक की कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन सतर्कता और ऊर्जा संरक्षण हमारा सामूहिक धर्म है। सरकार का यह स्पष्टीकरण अल्पकालिक राहत तो देता है लेकिन एक दीर्घकालिक प्रश्न भी छोड़ता है कि क्या हम हर संकट के समय केवल डैमेज कंट्रोल ही करते रहेंगे या भविष्य की नींव रखेंगे?

विकल्प नहीं, अनिवार्यता है वैकल्पिक ऊर्जा- वैश्विक ऊर्जा संकट और बढ़ती आयात निर्भरता के इस दौर में वैकल्पिक ऊर्जा अब केवल एक विकल्प नहीं बल्कि राष्ट्रीय अनिवार्यता बन चुकी है। ऊर्जा आत्मनिर्भरता ही सच्ची स्वतंत्रता का आधार है और भारत को इस दिशा में निर्णायक कदम उठाने होंगे। प्रधानमंत्री की मुफ्त बिजली योजनाएं और रूफटॉप सोलर मिशन केवल नीतिगत पहल नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सशक्त आधारस्तंभ हैं। भारत में 33 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता हैं, जो बड़े पैमाने पर आयातित ईंधन पर निर्भर हैं। यदि रसोई को इंडक्शन कुकिंग और एथनॉल आधारित विकल्पों की ओर मोड़ा जाए तो न केवल खर्च कम होगा बल्कि ऊर्जा आयात का बोझ भी घटेगा। लगभग 8 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली पर खाना बनाना एलपीजी की तुलना में किफायती है, वहीं कृषि अवशेषों से बनने वाला एथनॉल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकता है। इससे 'अन्नदाता' ही 'ऊर्जादाता' बन सकता है। परिवहन क्षेत्र में विद्युतीकरण भी उतना ही आवश्यक है। वर्तमान में तेल की सबसे अधिक खपत इसी क्षेत्र में होती है जबकि बिजली की हिस्सेदारी नगण्य है। यदि सार्वजनिक और वाणिज्यिक परिवहन को इलैक्ट्रिक किया जाए तो अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा बचाई जा सकती है। सौर ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे विकल्प भारत को स्थायी, स्वच्छ और सुरक्षित ऊर्जा भविष्य की ओर ले जा सकते हैं। अब समय आ गया है कि भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में निर्णायक परिवर्तन करे।

बिजली खपत का बदलता स्वरूप- भारतीय अर्थव्यवस्था में बिजली का 42 प्रतिशत हिस्सा उद्योगों में और 17 प्रतिशत कृषि में उपयोग होता है। जैसे-जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है, कार्यालयों और दुकानों (वाणिज्यिक क्षेत्र) में बिजली की मांग बढ़ेगी। हमें कोयला आधारित बिजली (जो अभी भी हमारी रीढ़ है) से हटकर परमाणु, सौर और पवन ऊर्जा की ओर तीव्र गति से मुड़ना होगा। सालाना 143 अरब डॉलर (2025 के आंकड़े) का तेल आयात एक ऐसा घाव है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को भीतर ही भीतर खोखला कर रहा है। सूर्य और पवन के रूप में भारत के पास असीमित प्राकृतिक संसाधन हैं लेकिन उन्हें 'ऊर्जा' में बदलने की इच्छाशक्ति और निवेश की गति अभी भी मंथर है।

भविष्य का रोडमैप: ऊर्जा सुरक्षा ही राष्ट्रीय सुरक्षा- ईरान-इजरायल युद्ध ने भारत के लिए एक कठोर चेतावनी प्रस्तुत की है। यदि होर्मुज जलडमरूमध्य बाधित होता है तो यह केवल क्षेत्रीय संकट नहीं रहेगा बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए 'आर्थिक प्रलय' का कारण बन सकता है। उर्वरक, ईंधन, सेमीकंडक्टर, हर आपूर्ति शृंखला पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में भारत को त्वरित, ठोस और दूरदर्शी कदम उठाने होंगे। सबसे पहले, रणनीतिक भंडार का सुदृढ़ीकरण अनिवार्य है। अगले 24 महीनों में कम से कम 90 दिनों का तेल और गैस रिजर्व तैयार करना राष्ट्रीय प्राथमिकता होनी चाहिए ताकि किसी भी वैश्विक व्यवधान के समय देश की ऊर्जा आवश्यकताएं प्रभावित न हों। दूसरा, ऊर्जा विविधीकरण पर आक्रामक रणनीति अपनानी होगी। रूस, मध्य एशिया और अफ्रीका जैसे क्षेत्रों के साथ दीर्घकालिक आपूर्ति समझौते, पाइपलाइन परियोजनाएं और वैकल्पिक व्यापार मार्ग विकसित करना समय की मांग है। तीसरा, परमाणु ऊर्जा, सौर शक्ति और ग्रीन हाइड्रोजन में निवेश को युद्ध स्तर पर बढ़ाना होगा। ये केवल स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत नहीं बल्कि स्थायी ऊर्जा सुरक्षा के स्तंभ हैं। अंततः, यह स्पष्ट है कि वैश्विक शांति हमारे नियंत्रण में नहीं परंतु अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना पूरी तरह हमारे हाथ में है। आत्मनिर्भरता अब केवल नारा नहीं बल्कि अस्तित्व की शर्त बन चुकी है। यदि हम आज निर्णायक कदम नहीं उठाते तो भविष्य का अंधकार हमारी ही निष्क्रियता का परिणाम होगा।

संक्षिप्त समाचार

रामा ग्रुप ने रायपुर में 'रामा ईको लग्ज़री फ्लोर्स' लॉन्च किया

रायपुर। रामा ग्रुप ने अपने फ्लैगशिप रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट 'रामा ईको' के तहत एक नए प्रीमियम फेज़ 'रामा ईको लग्ज़री फ्लोर्स' के लॉन्च की घोषणा की है। इस प्रोजेक्ट को RERA अप्रूवल मिल चुका है, जो एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। इसके साथ ही शंकर नगर, रायपुर के प्रमुख रेसिडेंशियल एरिया में 'रामाइ 'कोलग्ज़री फ्लोर्स'अल्ट्रा लक्ज़री अपार्टमेंट की बुकिंग शुरू हो गई है। नई दिल्ली के जाने-माने आर्किटेक्ट राजीव अग्रवाल (राजीव अग्रवाल आर्किटेक्ट्स) द्वारा डिजाइन किया गया यह प्रोजेक्ट मॉडर्न और रिफाइंड अर्बन होम्स के लिए जाना जाता है। वहीं, लैंडस्केप डिजाइनर, STGK, योकोहामा, जापान केस्टूडियो द्वारा तैयार किया गया है, जो अपने क्रॉस-डिसिप्लिनरी अप्रोच के लिए पहचाना जाता है। यह प्रोजेक्ट रेसिडेंट्स को एक प्राइवेट और एलीवेटेड लिविंग एक्सपीरियंस देने के उद्देश्य से बनाया गया है। 'रामा ईको लग्ज़री फ्लोर्स' की खास बात यह है कि हर फ्लोर पर सिर्फएक ही बड़ा अपार्टमेंट (4 & 5 BHK) दिया गया है, जिससे रेसिडेंट्स को पूरी प्राइवेसी और एक्सक्लूसिविटी मिलती है। इस प्रोजेक्ट में कुल 16 थॉटफुली प्लान्ड टावर्स हैं, जिनमें हर टावर में 7 फ्लोर्स हैं और कुल मिलाकर 112 अपार्टमेंट्स हैं। यह लो-डेंसिटी लिविंग कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इन अपार्टमेंट्स का साइज लगभग 7,100 स्क्वायर फीट से 12,800 स्क्वायर फीट तक है, जिनमें बड़े लिविंग एरियाज, बेडरूम्स और किचन स्पेसेस दिए गए हैं। साथ ही 12 फीट सीलिंग हाइट घर को और भी स्पेशियस और एयरी फील देती है।

इस गर्मी समझदारी से खाएँ इस प्रोटीन से भरपूर डाइट के साथ

नईदिल्ली। गर्मी इस बार जल्दी आ गई है, और बीच ट्रिप्स सामने हैं, ऐसे में अपनी फिटनेस रूटीन शुरू करने का यह बिल्कुल सही समय है। जहाँ जिम सेशन ज़रूरी हैं, वहीं डाइट भी स्वस्थ शरीर का वजन बनाए रखने और उसे बेहतर आकार देने में उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रितिका समद्दार, रीजनल हेड डाइटेटिक्स मैक्स हेल्थकेयर – नई दिल्ली कैलिफ़ोर्निया बादाम, ग्रीक योगर्ट और सैल्मन से भरपूर इस आसान, प्रोटीन से भरपूर प्लान की सिफारिश करती हैं।

सुबह की शुरुआत: कैलिफ़ोर्निया बादाम और उबले अंडे- अपने दिन की शुरुआत कुछ कैलिफ़ोर्निया बादाम के साथ करें। प्रोटीन, हेल्दी फैट, विटामिन ई और मैग्नीशियम से भरपूर ये बादाम ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने में मदद करते हैं, बिना अचानक ऊर्जा बढ़ने के। यह किसी भी फिटनेस-फोकस्ड डाइट के लिए एक बेहतरीन जोड़ हैं। इन्हें दो उबले अंडों के साथ मिलाएँ ताकि आपको पूरा प्रोटीन मिल सके। यह कॉम्बिनेशन पोर्टेबल, पेट भरने वाला और व्यस्त सुबहों के लिए परफेक्ट है।

दोपहर का भोजन: ग्रिल्ड चिकन ब्रेस्ट सलाद- ग्रिल्ड चिकन ब्रेस्ट को मिक्स्ड ग्रीन्स, चेरी टमाटर और खीरे के साथ टॉस करें। यह हेल्दी मील आपको लीन प्रोटीन, फाइबर और सब्ज़ियों से हाइड्रेशन देता है, जिससे आप हल्का महसूस करें और दोपहर तक ताजगी और संतुष्टि बनी रहे।

शाम का नाश्ता: चिया सीड्स के साथ ग्रीक योगर्ट- दोपहर के अंत में अपनी ऊर्जा को फिर से बढ़ाएँ, एक टीस्पून चिया सीड्स के साथ ग्रीक योगर्ट के साथ। यह नाश्ता आपके पेट के स्वास्थ्य के लिए प्रोबायोटिक्स, लंबे समय तक ऊर्जा और ताज़गी देने वाला ठंडक प्रभाव प्रदान करता है।

तनिष्क ने अपने नए कलेक्शन 'ह्यूज़' में आधुनिक भारतीय महिला के लिए प्राकृतिक जेमस्टोन आभूषणों को दी एक नई पहचान

नईदिल्ली। भारत का अग्रणी ज्वेलरी ब्रांड और टाटा परिवार का एक हिस्सा, तनिष्क ने अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर लेकर आया है, प्राकृतिक रंगीन जेमस्टोन्स का जादू – अपना नया और खास कलेक्शन 'ह्यूज़'! भारतीय ग्राहकों की जेमस्टोन्स के प्रति लगातार बढ़ती रूचि को देखते हुए, प्रस्तुत किया गया, 100 प्रतिशत प्राकृतिक जेमस्टोन्स से सजा यह कलेक्शन शुद्धता और बेहतरीन डिज़ाइन के प्रति तनिष्क की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आज की आधुनिक महिलाएँ अपनी एक अलग और खास पहचान चाहती हैं, और तनिष्क का यह अंदाज़ उनकी इसी पसंद को ध्यान में रखकर बनाया गया है। चाहे ऑफिस का डेली लुक हो या किसी खास फंक्शन की रौनक, ये जेमस्टोन्स आपके हर पल को खास बना देंगे। यह कलेक्शन भारतीय गर्मी के मौसम के रंगों और उसके खुलेपन से प्रेरित है। इन रंगों और एहसास को आधुनिक और कलात्मक डिज़ाइनों में ढाला गया है। हर आभूषण के केंद्र में एक जेमस्टोन है। जेमस्टोन्स की प्राकृतिक चमक और गहराई को निखारने के लिए उसके आस-पास की बनावट और शेप को बहुत बारीकी से तैयार किया गया है। इस कलेक्शन में आपको जेमस्टोन्स की कई तरह की कट्स का जादू देखने को मिलता है — चाहे वो क्लासिक 'मार्कीज़' (marquise) हो, बारीकी से तराशा गया 'ताबीज़' (tabiz) कट हो या रेशमी एहसास वाले 'कैबोचोन' (cabochon) स्टोन्स।

दंतेवाड़ा : साप्ताहिक समय-सीमा बैठक संपन्न

पर्यटन स्थलों में साफ-सफाई एवं प्लास्टिक क उपयोग को रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही करें अधिकारी-कलेक्टर

दंतेवाड़ा (समय दर्शन)। कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव की अध्यक्षता में आज संयुक्त जिला कार्यालय क डंकनी सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बैंक खातों के मिलान हेतु निर्देश जारी के संबंध में कहा गया कि स्थायी वित्त निर्देश 06, 2024 क तहत सभी संबंधित अधिकारियों को बैंक खातों क स्टेटमेंट का कशबुक एवं कार्यालय लेखों से मिलान निश्चित समय सीमा कर लेवें। इसक साथ ही बैंक समाधान विवरण प्रस्तुत करने एवं खातों क प्रकटन से संबंधित आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को भी कहा गया। इस जारी निर्देशों क अनुसार, सभी खातों की जांच

एवं मिलान (रिकॉन्सिलिएशन) 31 दिसंबर 2025 तक की स्थिति में पूर्ण किया जाना अनिवार्य है।

इसक साथ ही बैठक में कलेक्टर द्वारा जिले क मुख्य पर्यटन स्थलों में स्वच्छता सुनिश्चित करने क संबंध में कहा गया कि इसक लिए पर्यटन स्थलों में पर्यटन गतिविधियां संचालित करने वाली पंचायतों की ओर से स्वच्छता टीम का गठन किया जाए जो न कवल स्थलों की साफसफाई करेगी साथ ही साथ वहां आने वाले पर्यटकों को प्लास्टिक क उपयोग को रोकने क संबंध में कार्यवाही करेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि जिले क दर्शनीय स्थलों में प्लास्टिक बोतले, पॉलीथिन क जमाव से स्थलों की प्राकृतिक सुंदरता प्रभावित हो रही है। इसे रोकने क लिए प्रशासनिक प्रयास जरूरी है। यह भी कहा कि मुख्यालय में स्थित माई दंतेश्वरी क मंदिर तट पर स्थित शंकर नदी में भी फूल सहित अन्य पूजा सामग्रियों को प्रवाहित कर दिया जाता है यह भी पर्यावरण एवं स्वच्छता की दृष्टि से उचित नहीं है। इन सब उपयोग किए गए पूजा सामग्रियों फुल आदि क सुरक्षित निस्तारण हेतु कार्य योजना बनाएं। इसके साथ ही बैठक में नागरिक आपूर्ति निगम से भंडारण रिपोर्ट की अद्यतन जानकारी अपडेट करने, जिले क 33 शहीद परिवारों में से जिनक पास पूर्व से ही बोर सुविधा हो उन्हें तारबाड़ी फेसिंग, की सुविधा उपलब्ध कराने, मिलेट कैफे में विद्युतीकरण, जनगणना के संबंध में नियुक्त प्रगणकों की टीम को प्रशिक्षण क संबंध में भी कलेक्टर द्वारा दिशा निर्देश दिए गए।

प्रतिभावान छात्रों को मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

जगदलपुर (समय दर्शन)। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों क लिए तैयार करने और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने क उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 क लिए श्मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजनाश् (पूर्व में जवाहर उत्कर्ष योजना) क क्रियान्वयन हेतु प्रदेश क प्रतिष्ठित निजी आवासीय विद्यालयों से इम्पैनलमेंट के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। इस योजना क अंतर्गत छत्तीसगढ़ में स्थित सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त उन उत्कृष्ट निजी विद्यालयों का चयन किया जाएगा, जहाँ शिक्षण संस्थान और छात्रावास एक ही परिसर में संचालित हो रहे हों। विभाग द्वारा इस वर्ष कक्षा 6वीं में प्रवेश क लिए कुल 200 विद्यार्थियों का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें अनुसूचित जनजाति वर्ग क 130 और अनुसूचित जाति वर्ग क 70 विद्यार्थियों को इन चयनित संस्थानों में प्रवेश दिलाकर उन्हें कक्षा 12वीं तक नि:शुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान की जाएगी। चयनित विद्यालयों को विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी। संस्थाओं क चयन क लिए कड़े मापदंड निर्धारित किए गए हैं, जिसमें विद्यालय का कम से कम 5 वर्ष पुराना होना, स्वयं का सुसज्जित भवन, डिजिटल क्लासरूम, खेल मैदान और मानक स्तर क पृथक बालक-बालिका छात्रावास होना अनिवार्य है। इसक अतिरिक्त, विगत तीन वर्षों का बोर्ड परीक्षा परिणाम 80 प्रतिशत से अधिक होना और विद्यार्थियों क लिए विशेष कोचिंग व गुणवत्तापूर्ण भोजन की व्यवस्था जैसे मानकों पर 100 अंकों क आधार पर विद्यालयों का श्रेणीकरण किया जाएगा।

अवैध रेत उत्खनन पर सख्त कार्रवाई : 7 वाहन जब्त, प्रकरण दर्ज

दंतेवाड़ा (समय दर्शन)। कलेक्टर केनिर्देशानुसार जिले में अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण क लिए खनिज जांच दल द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में भैंरमबंद, बालूद एवं बालपेट क्षेत्रों में औचक निरीक्षण क दौरान गौण खनिज साधारण रेत का अवैध उत्खनन एवं परिवहन करते हुए 7 वाहनों को पकड़ा गया। खनिज जांच दल ने मौक पर पंचनामा तैयार कर संबंधित वाहनों को जब्त किया तथा सुरक्षार्थ कलेक्टर परिसर दंतेवाड़ा में रखा गया है। सभी मामलों में वाहन चालकों एवं मालिकों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। 05 एवं 06 अप्रैल 2026 को की गई कार्रवाई के दौरान संतोष ओढी (मुसकल), भिमसेन यादव (भैरमबंद), पवन शर्मा (दंतेवाड़ा), समलू सोढ़ी (चूडीटिकरा), शिवप्रसाद भास्कर (भैरमबंद), महेश भोगामी (मंगनार) एवं पुरन भास्कर (मंगनार) क ट्रैक्टर एवं ट्रैक्टर-लोडर वाहन अवैध रेत परिवहन करते पाए गए, जिन्हें जब्त किया गया।उक्त सभी मामलों में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 (4) के तहत वाहनों को जब्त करते हुए धारा 21 (5) के अंतर्गत आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन द्वारा पूर्व में भी खनिज ठेकदारों एवं परिवहनकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि बिना वैध अभिवहन पास क खनिजों का परिवहन दण्डनीय अपराध है। इसक बावजूद नियमों का उल्लंघन करने वालों क विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। कलेक्टर कहा कि जिले में अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर रोक लगाने हेतु खनिज अमले द्वारा निरंतर जांच एवं निगरानी की जा रही है तथा आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी।

किसानों ने खेतों की जल निकासी की समस्या के समाधान हेतु जनदर्शन में लगाई गुहार

दुर्ग (समय दर्शन) । जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंचे जनसामान्य लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने जनदर्शन में पहुंचे सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और समुचित समाधान एवं निराकरण करने संबंधित विभागों को शीघ्र कार्यवाही कर आवश्यक पहल करने को कहा। जनदर्शन में अपर कलेक्टर श्री विरेन्द्र सिंह भी उपस्थित थे। जनदर्शन में अवैध कब्जा, आवासीय पट्टा, प्रधानमंत्री आवास, भूमि सीमांकन कराने, सीसी रोड निर्माण, ऋण पुस्तिका सुधार, आर्थिक सहायता राशि दिलाने सहित विभिन्न मांगों एवं समस्याओं से संबंधित आज 140 आवेदन प्राप्त हुए। इसी कड़ी में जुनवानी-खम्हरिया मार्ग चौड़ीकरण से प्रभावित वार्ड क्रमांक 1 के निवासियों ने पुनर्व्यवस्थापन की मांग की। उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा जुनवानी खम्हरिया नगर होते हुए आईआईटी भिलाई पहुंच मार्ग के दोनों तरफ प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण से करीब 50 वर्षों से रह रहे कई मकान और दुकान प्रभावित होंगे। रहवासियों ने वैकल्पिक व्यवस्था कराकर कब्जा खाली कराकर निर्माण कार्य शुरू कराने के लिए आवेदन दिया। इस पर कलेक्टर ने ईई लोक निर्माण विभाग को कार्यवाही करने को कहा। कोलिहापुरी के किसानों ने खेतों से पानी निकासी की समस्या के समाधान कराने आवेदन दिया। किसानों ने बताया कि कोलिहापुरी गांव में वालफोर्ट मंगलम सिटी का निर्माण होने के कारण बॉड्रीवाल का निर्माण किया जा रहा है, जिसके कारण किसानों के खेतों में बारिश का पानी निकासी नही हो पा रहा है। लगभग 100 किसानों की खेती प्रभावित हो रही है। किसानों ने पानी निकासी की व्यवस्था कराने की मांग की, ताकि उनकी कृषि प्रभावित न हो। इस पर कलेक्टर ने निरीक्षण कर तहसीलदार दुर्ग को आवश्यक कार्यवाही करने कहा।

वृंदा नगर बोरसी में वार्डवासियों ने नाले के गंदे पानी के तालाब में सीधे जाने की समस्या को लेकर कार्यवाही करने की मांग की। बस्ती का गंदा पानी नाली के माध्यम से सीधे तालाब में प्रवाहित हो रहा है, जिससे तालाब का पानी अत्यधिक दुषित एव अनुपयोगी हो चुका है।

सैमसंग इंडिया ने लॉन्च किया 5 मोशन विंड के साथ बीस्पोक एआई विंडफ्री प्रो एसी, प्रीमियम होम कूलिंग को मिला नया अंदाज

गुरुग्राम: भारत के सबसे बड़े कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड सैमसंग ने आज होम कूलिंग में अपने नए प्रोडक्ट – 5 मोशन विंड के साथ बीस्पोक एआई विंडफ्री प्रो एयर कंडीशनर लॉन्च किया है। यह प्रीमियम एयर कंडीशनर आधुनिक लग्ज़री डिजाइन के साथ आता है, जो आज के जमाने के लिविंग स्पेस के लिए खासतौर पर तैयार किया गया है। इसका सुंदर और मिनिमलिस्ट डिजाइन किसी भी आधुनिक इंटीरियर में आसानी से घुल-मिल जाता है और स्थान की खूबसूरती बढ़ाता है। इस एसी में एडवांस्ड मोशन विंड टेक्नोलॉजी, एआई-पावर्ड कूलिंग इंटेलिजेंस और विंडफ्री कूलिंग का संयोजन है जोकि लग्ज़री और पर्सनलाइज्ड कूलिंग अनुभव देता है। इसका यूनिक मोशन ब्लेड डिजाइन एयरफ्लो को ऑप्टिमाइज करता है, जिससे वातावरण पूरी तरह साफ होता है और मीडियम से बड़े साइज के स्पेस में कुशल एयर क्लीनिंग मिलती है। सैमसंग इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट – डिजिटल अप्लायंसेज, घुफ्रान आलम ने कहा, सैमसंग भारत में अपनी 30वीं सालगिरह मना रहा है, और कंपनी ने नए-नए प्रोडक्ट विकसित करना और ग्राहकों को उनकी जरूरतों के मुताबिक बेहतरीन समाधान देना जारी रखा है। यहां पड़ने वाली चिलचिलाती गर्मी में उपभोक्ता सिर्फ कूलिंग नहीं, बल्कि इंटेलिजेंट, पर्सनलाइज्ड और एनर्जी-एफिशिएंट समाधान चाहते हैं। हमारा नया बीस्पोक एआई विंडफ्री प्रो एयर कंडीशनर प्रिसीजन एयरफ्लो और स्मार्ट टेक्नोलॉजी को जोड़कर तेज कूलिंग, ड्राफ्ट-फ्री कम्फर्ट और बिजली की बेहतर बचत देता है।

सैमसंग की एडवांस्ड मोशन विंड तकनीक कमरे में हवा की दिशा और स्पीड को अपने आप एडजस्ट करती है, जिससे ठंडक हर कोने में संतुलित और आरामदायक बनी रहती है। इसमें पांच अलग-अलग एयरफ्लो मोड मिलते हैं—जैसे मैक्स विंड, जो तुरंत तेज़ ठंडक देता है, और सराउंड विंड, जो हवा को पूरे कमरे में समान रूप से फैलाता है। वहीं, हल्की और सॉफ्ट ठंडक के लिए विंडफ्री कूलिंग दिया गया है, जिसमें 23,000 माइक्रो-होल्स के जरिए हवा बिना झोंके के धीरे-धीरे फैलती है, जिससे स्टिल एयर जैसा आरामदायक अनुभव मिलता है।

5 मोशन विंड के साथ बीस्पोक एआई विंड फ्री प्रो एयर कंडीशनर में एआई फास्ट एवं कम्फर्ट कूलिंग फीचर है, जो तापमान, नमी और कमरे के साइज़ का बुद्धिमानी से विश्लेषण करके अपने आप सबसे उपयुक्त कूलिंग मोड चुन लेता है।

न्यायाधीश अरविंद कुमार वर्मा के सम्मान में विदाई समारोह का किया गया आयोजन

दुर्ग (समय दर्शन) । छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में माननीय श्री न्यायाधीश अरविंद कुमार वर्मा के सेवानिवृत्ति के अवसर पर उनके सम्मान में विदाई कार्यक्रम का आयोजन माननीय श्री मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा के न्यायालय कक्ष में अपराह्न 03.30 बजे संपन्न हुआ। इस अवसर पर माननीय श्री न्यायाधीश रमेश सिन्हा मुख्य न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर ने अपने प्रेरणादायक उद्बोधन में न्यायाधीश अरविंद कुमार वर्मा के समग्र जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके विधिक ज्ञान, निष्पक्षता एवं प्रशासनिक दक्षता की सराहना एवं उनके योगदान की प्रशंसा करते हुए उनके भावी जीवन हेतु शुभकामनाएँ दी। माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने अभिव्यक्त किया कि

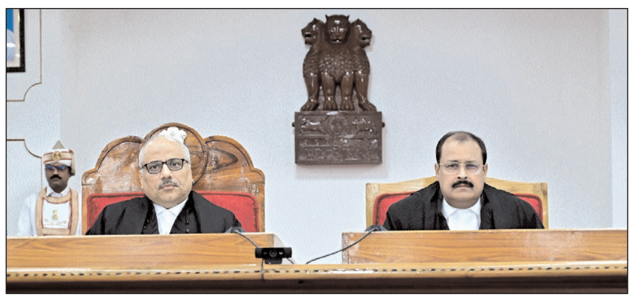

न्यायाधीश अरविंद कुमार वर्मा का न्यायिक जीवन उत्कृष्टता, निष्ठा और न्याय के प्रति अटूट समर्पण से परिपूर्ण रहा है, वे अपने कार्यकाल के दौरान स्पष्टता, संतुलित दृष्टिकोण तथा विधि के शासन के प्रति सम्मान के लिए जाने जाते हैं और अपने सम्पूर्ण न्यायिक जीवन में न्यायाधीश अरविंद कुमार वर्मा अपनी शालीनता, अनुशासनात्मक दृष्टिकोण एवं संस्था के प्रति गहरे सम्मान के लिए विख्यात रहे हैं। उनके निर्णय न केवल विधिक विवेचन तक सीमित रहे, बल्कि उनमें न्याय की मानवीय समझ भी परिलक्षित होती रही है। माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने यह भी कहा कि उनके निर्णयों ने व्यवस्था को सुदृढ़ किया तथा उनका आचरण युवा न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रेरणास्त्रोत बना और अपने कार्यकाल में न्यायाधीश अरविंद कुमार वर्मा ने विधि के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक उल्लेखनीय निर्णय दिए, कुल 9,800 से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया, जिनमें 238 ए.एफ.आर. निर्णय भी सम्मिलित हैं, ये आंकड़े मात्र संख्यात्मक उपलब्धियाँ नहीं, बल्कि उनके न्यायिक दृष्टिकोण एवं संवैधानिक मूल्यों के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। माननीय श्री न्यायाधीश अरविंद कुमार वर्मा ने अपने उद्बोधन में ईश्वर, माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा एवं समस्त माननीय न्यायाधीशगण, परिवार, न्यायिक अधिकारीगण, सहयोगियों, अधिवक्ताओं एवं न्यायालय परिवार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपने कार्यकाल के अनुभव साझा किए। उल्लेखनीय है कि माननीय श्री न्यायाधीश अरविंद कुमार वर्मा का जन्म 08 अप्रैल, 1964 को अंबिकापुर (छत्तीसगढ़) में हुआ, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा शासकीय बहुउद्देश्यीय विद्यालय, अंबिकापुर से प्राप्त की, तत्पश्चात अंबिकापुर महाविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने शासकीय राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अंबिकापुर से विधि शिक्षा प्राप्त की। वर्ष 1994 में उन्होंने व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-द्वद्व के रूप में न्यायिक सेवा प्रारंभ की। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने घरघोड़ा, राजनांदगांव, रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर में विभिन्न पदों पर कार्य किया एवं कॉमर्शियल कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश के रूप में पदस्थ रहे हैं। उन्होंने जगदलपुर, बिलासपुर एवं रायपुर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में भी सेवाएं प्रदान की।

माननीय श्री न्यायाधीश अरविंद कुमार वर्मा ने माननीय उच्च न्यायालय में रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्रार न्यायिक एवं छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी के अतिरिक्त निदेशक के पद पर प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन किया। दिनांक 23 जनवरी 2024 को वे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए तथा 12 दिसंबर 2025 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के समस्त माननीय न्यायाधीशगण, माननीय श्री न्यायाधीश अरविंद कुमार वर्मा के परिवार के सदस्यगण, महाधिवक्ता, अध्यक्ष उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ, डिप्टी सॉलिसिटर जनरल, वरिष्ठ अधिवक्तागण, अधिवक्तागण, प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी कार्य विभाग, रजिस्ट्रार जनरल, आदि अधिकारीगण उपस्थित थे।

संक्षिप्त समाचार

ट्रंप की धमकियों पर फिर भड़का ईरान, तेहरान की महिला प्रोफेसर का कड़ा जवाब

तेहरान, एजेंसी। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड

ट्रंप की कड़ी चेतावनियों पर ईरान से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। तेहरान विश्वविद्यालय की महिला सहायक प्रोफेसर सेतारेह सादेकी ने साफ कहा कि हमारे सिर पर बंदूक रखकर बातचीत की बात करना ईरान के लिए कभी स्वीकार्य नहीं होगा। दरअसल, ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि यदि मंगलवार रात तक कोई समझौता नहीं हुआ तो ईरान के बुनियादी ढांचे को गंभीर नुकसान झेलना पड़ेगा। उन्होंने यहां तक कहा कि एक रात में ईरान को खत्म कर सकते हैं। सादेकी ने कहा कि अमेरिका की ये धमकियां कोई नई बात नहीं हैं, बल्कि पहले दिए गए डेडलाइन का विस्तार हैं। उनके मुताबिक ईरान इसे ऐसे देखता है जैसे हमारे सिर पर बंदूक तानकर बातचीत करने को कहा जा रहा हो, जो कभी काम नहीं करेगा। उन्होंने दोहराया कि जब तक ईरान के शहरों पर हमले और बमबारी जारी रहेगी, तब तक अमेरिका के साथ न तो बातचीत होगी और न ही किसी युद्धविराम पर सहमति बनेगी। तेहरान यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर ने अमेरिका पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि हाल के हमलों में विश्वविद्यालयों, रिसर्च सेंटर, टीकाकरण केंद्रों और पुलों को निशाना बनाया गया है। सादेकी के अनुसार, संभावना है कि अमेरिका आगे भी नागरिक ढांचे पर हमले तेज कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान ने पहले भी अमेरिकी हमलों का जवाब प्रभावी तरीके से दिया है। ईरान ने क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों और इस्राइली इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर अपनी क्षमता दिखाई है। सादेकी ने चेतावनी दी कि ईरान भविष्य में भी ऐसे ही जवाब देगा जिससे अमेरिका की हमले करने की क्षमता कमजोर हो सके। व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह क्रिटिकल पीरियड है और ईरान को समझौते के लिए पर्याप्त समय दिया गया है। उन्होंने कहा हमने उन्हें 10 दिन दिए हैं। अब उनके पास मंगलवार रात 8 बजे (ईस्टर्न टाइम) तक का समय है। इसके बाद उनके पास न पुल होंगे, न पावर प्लांट।

चीन ने 40 दिन के लिए ताइवान का हवाई क्षेत्र बंद किया, क्या किसी साजिश की आशंका?

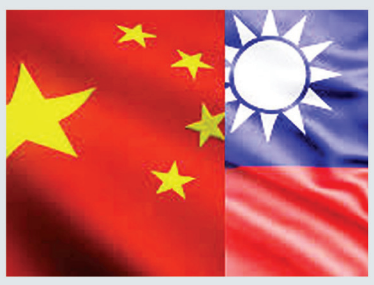

बीजिंग/ताइपे, एजेंसी। दुनिया जहां पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष पर ध्यान लगाए हैं वहीं चीन इस फिराक में है कि वह अपने एक चीन एजेंडे को कैसे अमल में लाए। इसके लिए उसने ताइवान द्वीप के पास 40 दिनों के लिए हवाई क्षेत्र बंद करने का कदम उठाया है। बता दें, ताइवान को चीन अपना ही क्षेत्र मानता है और इस जलक्षेत्र में अपने लड़ाकू विमान तथा जंगी विमानवाहक पोत भेजता रहा है। उसने छह मई तक यह बड़ा हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रविवार की एक रिपोर्ट के अनुसार, चीन ने बिना कोई स्पष्टीकरण दिए अपने क्षेत्र को 40 दिनों के लिए बंद करने का नोटिस जारी किया है। यह हवाई क्षेत्र दक्षिण कोरिया के पास पीत सागर से जापान के पास पूर्वी चीन सागर तक फैला हुआ है। चीन का यह कदम ये ऐसे वक्त हो रहा है जबकि अमेरिका इन दिनों ईरान में उलझा हुआ है और इस क्षेत्र से सैन्य साजो सामान भी पश्चिम एशिया ले जाया गया है। पहले ऐसे हवाई क्षेत्र की बंदी सैन्य अभ्यासों के लिए महज कुछ दिनों की ही होती थी। इतने लंबे हवाई क्षेत्र की बंदी के फैसले के पीछे की वजह चीनी विदेश मंत्रालय ने किसी को नहीं बताई है। आशंका है कि चीन मौजूदा हालात में ताइवान पर आक्रामक हो सकता है।

कोमा में है मोजतबा खामेनेई, कोम शहर में चल रहा सर्वोच्च नेता का इलाज; रिपोर्ट में बड़ा दावा

लंदन, एजेंसी। ईरान के नए सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई गंभीर रूप से घायल हैं। एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि मोजतबा खामेनेई वर्तमान में कोम शहर में इलाज करवा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार खामेनेई अचेत अवस्था में हैं और उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। माना जा रहा है कि इसी वजह से मोजतबा किसी भी निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने में असमर्थ हैं।

'द टाइम्स यूके' की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह कूटनीतिक मेमो अमेरिकी और इस्राइली खुफिया एजेंसियों द्वारा खाड़ी सहयोगियों के साथ साझा की गई जानकारी पर आधारित है। इस रिपोर्ट में पहली बार सर्वोच्च नेता के ठिकाने का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोजतबा खामेनेई का कोम शहर में इलाज चल रहा है और इस वजह से वे शासन के किसी भी निर्णय में शामिल नहीं हो पा रहे हैं।

मोजतबा की सार्वजनिक अनुपस्थिति ने गहराया शक: पश्चिम एशिया में संघर्ष छिड़ने के बाद से मोतबा खामेनेई ने कोई सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है। उनके नाम से जारी किए गए संदेशों का प्रसारण ईरानी सरकारी मीडिया द्वारा किया जा रहा है। इसकी वजह से मोजतबा के गंभीर रूप से घायल होने की खबरों को और बल मिला है।

अमेरिकी रिपोर्टों में अलग-अलग दावे: ईरानी अधिकारियों ने बयान जारी कर कहा कि देश की कमान नए सर्वोच्च नेता के हाथ में है। इसके बावजूद कई अमेरिकी रिपोर्टों में खामेनेई की सेहत पर सवाल खड़े किए हैं। किसी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मोजतबा कोमा में हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं, द सन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि हमलों में खामेनेई ने एक हाथ और एक पैर खो दिया है।

ट्रंप ने दी तबाही मचाने की चेतावनी: यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को मंगलवार आठ बजे (ईस्टर्न टाइम) तक एक समझौता करने का अल्टीमेटम दिया है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि इस समय सीमा के बाद कोई पुल और कोई बिजली संयंत्र नहीं बचेगा। ट्रंप ने स्वीकार किया कि संघर्ष 28 फरवरी को शुरू होने पर ईरान बहुत शक्तिशाली स्थिति में था, लेकिन अब अमेरिका ने उसके सिर को काट दिया है। उन्होंने कहा कि ये कदम 47 साल पहले ही उठाए जाने चाहिए थे। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि यह ठीक चल रहा है, लेकिन हमें देखना होगा।

आर्टेमिस II: इंसान ने चांद के उस हिस्से का किया दीदार, जिसे पहले किसी ने नहीं देखा

ह्यूस्टन, एजेंसी। चांद मिशन के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बन गया है। नासा के मिशन आर्टेमिस सेकंड ने इंसानों को पृथ्वी से अब तक की सबसे ज्यादा दूरी तक पहुंचा दिया है। इस मिशन ने अपोलो 13 का पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। नासा की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार जैसे ही अंतरिक्ष यात्री चांद के पास पहुंचे, उनके सामने खिड़कियों से चांद का शानदार नजारा दिखाई देने लगा। खास बात यह रही कि इस दौरान उन्हें चांद के उस हिस्से (फार साइड) को देखने का मौका मिला, जिसे पहले इंसानों ने कभी इस तरह करीब से नहीं देखा था। यह पूरा फ्लाईबाय करीब छह घंटे तक चला, जो इस मिशन का सबसे अहम हिस्सा माना जा रहा है। इस मिशन में तीन अमेरिकी और एक कनाडाई अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं, जो मिलकर इस ऐतिहासिक यात्रा को अंजाम दे रहे हैं। यह मिशन नासा की उस बड़ी योजना का हिस्सा है, जिसके तहत एक बार फिर इंसानों को चांद पर उतारने की तैयारी की जा रही है। खास तौर पर चांद के साउथ पोल (दक्षिणी ध्रुव) पर अगले दो साल में इंसानों के कदम रखने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि नासा के आर्टेमिस मिशन के अंतरिक्ष यात्री अब पृथ्वी से सबसे दूर पहुंचने वाले इंसान बन गए हैं। (भारतीय समयानुसार रात लगभग 11:27 बजे) उन्होंने 1970 में अपोलो 13 द्वारा बनाया गया रिकॉर्ड तोड़ दिया। नासा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में बताया कि उनका यह मिशन चांद के दूरवर्ती हिस्से (फार साइड) के चारों ओर यात्रा करता हुआ।

ट्रंप के हमलों से निपटने के लिए ईरान में बनेगी मानव श्रृंखला, ढाल का करेंगे काम

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका और इस्राइल के हमले में अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान के नए सर्वोच्च नेता चुने गए मोजतबा खामेनेई की सेहत पर संशय बरकरार है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि बमबारी में वे गंभीर रूप से घायल हुए, जिसके बाद उनके कई अंगों को नुकसान पहुंचा। कुछ खबरों में मोजतबा के कोमा में होने और यहां तक की एक पैर काटने की नौबत आने की बात भी सामने आई। हालांकि, ईरान की तरफ से इस संबंध में कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है। युद्ध के 39वें दिन आई कुछ और रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। संघर्षविराम और युद्ध को लेकर मोजतबा किसी तरह की प्रतिक्रिया देने की स्थिति में नहीं है। यहां तक कि उनके सटीक ठिकाने का भी पता लगाया जा चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने की समयसीमा नजदीक आने से पहले ईरान ने बड़ी योजना बनाई है। तेहरान ने कथित तौर पर युवा ईरानियों से ईरान के प्रमुख बिजली संयंत्रों के चारों ओर प्रतीकात्मक मानव श्रृंखला बनाने का आह्वान किया है। ईरान के खेल और युवा मंत्रालय ने एथलीटों, कलाकारों और छात्रों सहित देश के युवाओं से मंगलवार को दोपहर दो बजे (स्थानीय समय) से इन स्थलों के आसपास इकट्ठा होने का आह्वान किया है। ईरान के युवा मामलों के उप मंत्री अलीरेजा रहीमी ने एक वीडियो संदेश में कहा, 'कई विश्वविद्यालय के युवाओं, युवा कलाकारों और युवा संगठनों ने प्रस्ताव दिया कि हम देश के बिजली संयंत्रों के चारों ओर एक मानव घेरा या मानव श्रृंखला बनाएं। 'न्यूजीलैंड बोला- ईरानी बुनियादी ढांचे के खिलाफ अमेरिकी धमकियां 'निरर्थक' न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री

क्रिस्टोफर लक्सन ने ईरानी नागरिक अवसंरचना के खिलाफ ट्रंप की हालिया धमकियों को निरर्थक बताया है। उन्होंने कहा कि यह मददगार नहीं है, क्योंकि और अधिक सैन्य कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि मूल बात यह है कि इस संघर्ष को और अधिक फैलने से रोकने पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है।' उन्होंने कहा कि इस सप्ताह वॉशिंगटन में होने वाली बैठक में न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स का अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो को संदेश होगा कि संघर्ष को कम किया जाए। जापान ने मंगलवार को कहा कि जनवरी से ईरान में हिरासत में लिए गए एक जापानी नागरिक को रिहा कर दिया गया है। मुख्य कैबिनेट सचिव मिनोरू किहारा ने पत्रकारों को बताया कि उनकी रिहाई की पुष्टि सोमवार को हुई थी। जिस व्यक्ति को रिहा किया गया है, वह जापान के एनएचके सार्वजनिक टेलीविजन में पत्रकार बताया जा रहा है। किहारा ने कहा कि व्यक्ति स्वस्थ है, लेकिन उन्होंने आगे कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया। अमेरिकी सेना ने ईरान युद्ध में अब तक 13,000 से अधिक लक्ष्यों पर हमले किए हैं। पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य अभियानों के लिए जिम्मेदार और ईरान पर हमलों का नेतृत्व कर रही अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसकी सेनाओं ने 13,000 से अधिक ईरानी ठिकानों पर हमला किया है। सेंट्रल कमांड ने यह भी कहा कि 155 से अधिक ईरानी जहाजों को नुकसान पहुंचाया गया है या नष्ट कर दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि अमेरिकी परमाणु-संचालित विमानवाहक पोत और पनडुब्बियां ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में भाग ले रही हैं।

डोनाल्ड ट्रंप ने भारत-पाक के बीच सुलह का फिर लिया श्रेय

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को एक बार फिर दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष को समाप्त कराया था। उन्होंने दावा किया कि इससे तीन से पांच करोड़ जिंदगियां बचीं। यह बयान ईरान के साथ जारी छह सप्ताह के युद्ध के बीच आया है। पिछले साल मई में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव तब बढ़ा था, जब नई दिल्ली ने पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। ट्रंप का यह दावा नया नहीं है; उन्होंने पहले भी कई बार कहा है कि उन्होंने इस संघर्ष को समाप्त कराया था, जबकि भारत सरकार ने इन दावों का खंडन किया है। व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा, 'मैंने भारत और पाकिस्तान सहित आठ संघर्षों को खत्म किया। इतना ही नहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे बताया कि मैंने तीन से पांच करोड़ लोगों की जान बचाई।' उन्होंने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूसरी बार इस दावे को दोहराया और कहा कि उन्होंने आठ युद्ध समाप्त किए। उन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने पर भी निराशा व्यक्त की।

नाटो पर फिर निकाला गुस्सा

ट्रंप ने यह भी कहा कि एक और युद्ध खत्म करना बाकी है। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि यह ईरान, यूक्रेन या कोई अन्य वैश्विक संघर्ष है। डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो सहयोगियों द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने में शामिल होने से इनकार करने और ईरान के खिलाफ अमेरिकी आक्रामक अभियानों में सहायता करने में उनकी हिचकिचाहट पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने अपने सहयोगी देशों से समर्थन की कमी पर भी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा, 'क्या आप जानते हैं कि किसी ने हमारी मदद नहीं की? दक्षिण कोरिया ने हमारी मदद नहीं की। ऑस्ट्रेलिया ने हमारी मदद नहीं की। जापान ने मदद नहीं की। हमने जापान में 50,000 सैनिक तैनात किए हैं, हमने दक्षिण कोरिया में 45,000 सैनिक तैनात किए हैं, ताकि किम जोंग उन से बचाया जा सके, जिनसे मेरी बहुत अच्छी बनती है। '

ईरान को दी भीषण हमलों की चेतावनी

ट्रंप ने ईरान को मंगलवार शाम आठ बजे की समयसीमा तक अमेरिका के साथ समझौता न करने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा, 'हमारे पास एक योजना है, जिसके तहत ईरान का हर पुल कल रात 12 बजे तक तबाह कर दिया जाएगा।' उन्होंने आगे कहा कि ईरान के बिजली संयंत्र 'जलते हुए, फटते हुए और फिर कभी इस्तेमाल न होने वाले' होंगे।

क्या ईरान पर ट्रंप की धमकियां बेअसर? आईआरजीसी बोली- सेना ने अमेरिकी-इस्राइली ठिकानों पर हमले किए

तेहरान, एजेंसी। ईरान ने कहा है कि उस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का कोई असर नहीं होगा। देश की सरकारी मीडिया पर जारी रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सेना- आईआरजीसी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के बयानों को 'आधारहीन' बताया है। ईरान की सेना ने कहा है कि ट्रंप की धमकियों से अमेरिका और इस्राइली सुरक्षाबलों के खिलाफ जारी आक्रामक कार्रवाई प्रभावित नहीं होगी। ईरान के मुताबिक धमकियों से पश्चिम एशिया में हुआ अमेरिका का अपमान नहीं मिटेगा। आईआरजीसी के खातम अल-अंबिया केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता- इब्राहिम जोल्फाघारी ने दावा किया कि इस्लामी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) नौसेना बलों ने इस्राइली कंटेनर जहाज एसडीएन 7 पर क्रूज मिसाइल से हमला किया। इस हमले से जहाज में बड़ी आग लग गई और वह नष्ट हो गया। अमेरिकी हमलावर जहाज एलएचए-7 भी दोनों पक्षों के बीच हुई भारी गोलाबारी की चपेट में आया। ईरानी सेना का कहना है कि उसके हमले के कारण अमेरिकी जहाजों को हिंद महासागर में पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। आईआरजीसी एयरोस्पेस फोर्स ने

उत्तरी और दक्षिणी तेल अवीव के प्रमुख स्थलों को निशाना बनाया। हाइफा के रणनीतिक केंद्रों और बीर शेवा के रासायनिक संयंत्रों पर भी हमला किया गया। आईआरजीसी के मुताबिक सेना ने पेता टिकवा में इस्राइली सैनिकों की एक टुकड़ी पर भी बैलिस्टिक मिसाइलों से सटीक हमला किए जाने का दावा किया। आईआरजीसी के मुताबिक ईरानी सेना की कार्रवाई- ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस चार के 98वें चरण में दो बार हमले किए गए। कुवैत में अमेरिकी अल-अदैरी बेस पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया गया।

फजीहत के बाद बदले पाकिस्तान के सुर, यूएस-ईरान समझौते पर अब किया टिप्पणी से इनकार

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान ने सोमवार को ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए शांति प्रस्ताव की खबरों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। हालांकि, विदेश कार्यालय ने कहा कि शांति प्रक्रिया जारी है। विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने कहा, '45 दिवसीय युद्धविराम की पेशकश या 15-सूत्रीय समझौते की कई खबरें आई हैं। हम इन पर टिप्पणी नहीं करते हैं।' पाकिस्तान का यह बयान रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें दावा किया गया था कि ईरान और अमेरिका को पाकिस्तान द्वारा तैयार की गई एक योजना मिली है, जो युद्धविराम करा सकती है। रिपोर्ट में एक सूत्र का हवाला देते हुए कहा गया है कि युद्धविराम की यह रूपरेखा रातोंरात दोनों पक्षों के साथ साझा की गई थी।

अमेरिकी मीडिया एक्सियोस ने अपनी एक रिपोर्ट में स्रोतों का हवाला देते हुए बताया था कि अमेरिका, ईरान और क्षेत्रीय मध्यस्थ एक संभावित 45-दिवसीय युद्धविराम पर चर्चा कर रहे थे। जो युद्ध को स्थायी रूप से समाप्त करने की दिशा में दो-चरणीय समझौते का हिस्सा हो सकता है। इसमें पहले युद्धविराम और फिर व्यापक समझौता किए जाने का दावा किया गया था।

ईरानी समाचार एजेंसी आईआरएनए के अनुसार मध्यस्थ पाकिस्तान के जरिए अमेरिका द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर जवाब देते हुए तेहरान ने युद्धविराम को खारिज कर दिया। ईरान ने कहा कि युद्ध का स्थायी अंत जरूरी है। ईरान के जवाब में 10 सूत्र शामिल थे, जिनमें क्षेत्र में संघर्षों की समाप्ति, होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित आवागमन के लिए एक प्रोटोकॉल, प्रतिबंधों को हटाना और पुनर्निर्माण शामिल थे।

मध्यस्थ बन रहे पाकिस्तान के युद्धविराम प्रस्ताव के जवाब में ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि बातचीत अल्टीमेटम और युद्ध अपराधों के अंजाम देने की धमकी के साथ असंगत है। प्रवक्ता इस्माइल बघेई ने कहा कि 15-सूत्रीय योजना जैसी पिछली अमेरिकी मांगों को बहुत ज्यादा होने की वजह से अस्वीकार कर दिया गया था। पाकिस्तान खुद को शांति प्रक्रिया में एक सूत्रधार के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान इस युद्ध में मध्यस्थ की भूमिका निभाकर अमेरिका के साथ अपने संबंधों और ईरान के साथ अपने कामकाजी संबंधों का लाभ उठा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी कि अगर एक निश्चित समयसीमा के भीतर युद्धविराम नहीं हुआ तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी कि अगर तेहरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से नहीं खोला तो अमेरिका उसके बिजली संयंत्रों और पुलों को निशाना बनाएगा।

मुझे मेरे जैसे और लोगों की जरूरत: ईरान पर अपने विवादित पोस्ट को लेकर घिरे ट्रंप

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने बयान को लेकर विवादों में आ गए हैं। इस बार मामला उनके उस सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने ईरान को लेकर बेहद कड़ी और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान ने युद्ध खत्म करने के लिए समझौता नहीं किया, तो उन्हें भारी तबाही का सामना करना पड़ेगा। इस बयान के बाद जब पत्रकारों ने उनसे आलोचना पर सवाल किया, तो ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें आलोचकों की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने कहा, 'मुझे आलोचकों की परवाह नहीं है।' जब उनसे यह भी पूछा गया कि कुछ लोग उनके मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठा रहे हैं, तो उन्होंने इसे भी नजरअंदाज करते हुए कहा कि अगर ऐसा है, तो देश को उनके जैसे और लोगों की जरूरत है। ट्रंप ने अपने बचाव में कहा कि उनके राष्ट्रपति बनने से पहले अमेरिका को व्यापार समेत कई मामलों में नुकसान उठाना पड़ रहा था, लेकिन उन्होंने आकर स्थिति बदली। उनका कहना था कि उनकी सख्त नीति और बयानबाजी ही अमेरिका के हित में है। हालांकि, उनके इस बयान के बाद विपक्ष और कई आलोचकों ने तीखी प्रतिक्रिया दी।

खासकर ईस्टर के दिन किए गए उनके सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर लोगों ने इसे घृणित और अशोभनीय बताया। कुछ नेताओं ने तो यहां तक मांग कर दी कि उनके मंत्रिमंडल को 25वां संशोधन का इस्तेमाल कर उन्हें पद से हटाने पर विचार करना चाहिए।

इस तनाव के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर उनके हाथ में फैसला होता, तो अमेरिका ईरान के तेल पर कब्जा कर सकता है, क्योंकि वह खुद को पहले बिजनेसमैन मानते हैं। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिका पहले भी वेनेजुएला के साथ तेल को लेकर साझेदारी कर चुका है, इसलिए ईरान के मामले में भी ऐसा किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि 'जंग जीतने वाले को उसका फायदा मिलना चाहिए' और अमेरिका को भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने साफ इशारा दिया कि अमेरिका अपनी पुरानी नीति से हटकर युद्ध के बाद संसाधनों पर कब्जा करने की सोच सकता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने दूसरे देशों की मदद की, लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए।

इस दौरान ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि ईरान के पास समझौता करने के लिए मंगलवार रात 8 बजे (भारतीय समयानुसार बुधवार सुबह 5:30 बजे) तक का वक्त है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस समय तक कोई डील नहीं होती, तो ईरान में 'न पुल बचेंगे, न पावर प्लांट' और देश पाषाण युग में पहुंच जाएगा। ट्रंप ने बताया कि ईरान ने पहले सात दिन का समय मांगा था, लेकिन अमेरिका ने उसे 10 दिन दिए। अब यह अंतिम समयसीमा है। उन्होंने कहा कि यह बहुत 'महत्वपूर्ण अवधि' है और अब फैसला ईरान को ही करना है।

राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी दावा किया कि जब यह संघर्ष 28 फरवरी को शुरू हुआ था, तब ईरान ज्यादा मजबूत था, लेकिन अब अमेरिका ने उसे कमजोर कर दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 47 वर्षों में जो कदम उठाए जाने चाहिए थे, वो अब किए जा रहे हैं। इसके अलावा, ट्रंप ने एक और बड़ा दावा किया कि ईरान के कुछ लोग खुद अमेरिका से कह रहे हैं कि 'बमबारी जारी रखें', क्योंकि वे अपने देश में आजादी चाहते हैं। उनके मुताबिक, ईरान में हालात बहुत खराब हैं और विरोध करने वालों पर सख्त कार्रवाई होती है। ट्रंप ने साफ कहा कि ईरान के साथ हुए युद्ध के दौरान नाटो और अमेरिका के करीबी देशों- जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया, ने अमेरिका का साथ नहीं दिया। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान युद्ध ने नाटो के साथ रिश्तों पर ऐसा असर डाला है, जो उनके मुताबिक कभी खत्म नहीं होगा। उन्होंने नाटो को पेपर टाइगर यानी कमजोर संगठन बताते हुए कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इससे नहीं डरते।

पहली सूची में 17 पदाधिकारियों को जिम्मेदारी, करन साहू बने संभागीय संयोजक

प्रदेश संयोजक द्वारिका साहू ने किया कार्यकारिणी विस्तार, दुर्ग संभाग के संयोजक बने पत्रकार करन साहू

दुर्ग (समय दर्शन)। छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ (आई.टी. सेल प्रकोष्ठ) द्वारा करन साहू को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपते हुए संभागीय संयोजक पद पर व अन्य 16 पदाधिकारियों की नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के अध्यक्ष डॉ. नीरेन्द्र साहू, आई.टी. सेल प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक द्वारिका साहू तथा प्रदेश पदाधिकारियों की सहमति एवं अनुमोदन से की गई है।

श्री करन वर्तमान में दुर्ग जिला के अम्लेश्वर नगर में प्रेस क्लब अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इससे पूर्व भी वे आई.टी. सेल प्रकोष्ठ में प्रदेश संगठन सचिव सहित स्थानीय और तहसील के कई महत्वपूर्ण दायित्वों का सफ्लतापूर्वक निर्वहन कर चुके हैं। संगठन को मजबूत बनाने, जनसंपर्क को विस्तार देने तथा तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

श्री करन साहू ने भावुकता व्यक्त करते हुए कहा कि दुर्ग जिले तहसील पाटन के धर्म नगरी ग्राम कौही से निकलकर एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलना उनके लिए गर्व और सम्मान का विषय है। उन्होंने समाज के शीर्ष नेतृत्व, वरिष्ठजनों एवं सभी शुभचिंतकों के प्रति आभार प्रकट किया साथ ही सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई व शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि माता कर्मा, माता राजिम, अपने माता-पिता, गुरुजनों एवं समाज के आशीर्वाद से मिली यह जिम्मेदारी उन्हें और अधिक समर्पण एवं ऊर्जा के साथ समाज सेवा करने की प्रेरणा देती है। इस नियुक्ति पर समाज के वरिष्ठजनों, जनप्रतिनिधियों एवं परिजनों ने हर्ष व्यक्त करते हुए श्री साहू को शुभकामनाएँ दीं तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

खबर-खास

आबंटन आया नहीं, चांवल के भटक रहे हितग्राही

पाटन (समय दर्शन)। क्षेत्र के कोपेडीह (कापसी) गांव में इन दिनों राशन वितरण को लेकर अव्यवस्था की स्थिति बनी हुई है। यहां के हितग्राहियों को अब तक चावल नहीं मिल पाया है, जिससे लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। जानकारी के अनुसार, फूड विभाग द्वारा चावल का आबंटन विलंब से किया गया, जिसके चलते वितरण प्रक्रिया प्रभावित हुई है। हालांकि विभाग का कहना है कि जल्द ही चावल का आबंटन शुरू कर दिया जाएगा और सभी पात्र हितग्राहियों को राशन उपलब्ध कराया जाएगा।

गांव के सरपंच ने बताया कि चावल नहीं मिलने के कारण हितग्राही रोजाना राशन दुकान के चक्कर लगा रहे हैं। सुबह से ही लोग दुकान पहुंचते हैं, लेकिन चावल नहीं मिलने पर वे सीधे सरपंच के घर पहुंचकर अपनी समस्या बता रहे हैं।

बताया जा रहा है कि पिछले महीने करीब पांच दिनों तक सर्वर मेंटनेंस के कारण सिस्टम बंद रहा, जिससे चावल वितरण में देरी हुई। अब हितग्राही जल्द से जल्द राशन वितरण शुरू होने की उम्मीद लगाए हुए हैं।

नवाचार में उत्कृष्ट कार्य पर सुमित्रा कश्यप को राज्य स्तरीय सम्मान

बिर्रा (समय दर्शन)। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए जैजैपुर विकासखंड अंतर्गत घिवरा स्थित शासकीय प्राथमिक शाला मिलपारा में पदस्थ प्रधान पाठिका श्रीमती सुमित्रा कश्यप को राज्य स्तरीय एफ़एलएन सह नवाचतन वारियर्स शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया ।यह प्रतिष्ठित सम्मान दुर्ग स्थित खालसा पब्लिक स्कूल में आयोजित गरिमामय समारोह में प्रदान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने श्रीमती कश्यप को प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया। श्रीमती कश्यप द्वारा बच्चों के सर्वांगीण विकास एवं बुनियादी साक्षरता (स्नस्न्) को मजबूत करने के लिए किए गए नवाचारी प्रयासों को राज्य स्तर पर सराहा गया है। उनके इस उल्लेखनीय कार्य से न केवल विद्यालय बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम गौरवान्वित हुआ है।

कलश यात्रा के साथ भागवत कथा का हुआ शुभारंभ, आचार्य उमाशंकर पाण्डेय विराजित हैं ब्यासपीठ पर

जांजगीर चांपा (समय दर्शन)। ग्राम

डोंगाकोहरौद के शिरीष पाठ मार्ग में स्थित धीवर परिवार निवास में श्रीमद भागवत कथा का शुभारंभ गत सात अप्रैल को कलश यात्रा के साथ हुआ जिसमें ब्यासपीठ पर गांव के ही आचार्य उमाशंकर पाण्डेय विराजित हैं । यह कथा काशीराम धीवर श्रीमती जता बाई , हिंछाराम उपासीन बाई धीवर परिवार द्वारा आयोजित है । कथा का समापन गीता पाठ , तुलसी वर्षा , सहस्त्र धारा , ब्राम्हण भोजन के साथ 14 अप्रैल को होगी । आयोजक परिवार ने कथा श्रवण का लाभ लेने समस्त ग्रामवासीयों से किया है ।

जंगल में चल रहा था 'सट्टा सिंडिकेट', — कांकेर में 3 आरोपी गिरफ्तार, नगदी और मोबाइल जब्त

कांकेर (समय दर्शन)। उत्तर बस्तर कांकेर के सिकसोड़ थाना क्षेत्र में सट्टा के संगठित खेल पर पुलिस ने बड़ा वार करते हुए जंगल के बीच चल रहे अवैध सट्टा नेटवर्क का भंडाफोड़ कर दिया, करेंगांव के पास भर्री सागौन प्लांटेशन इलाके में चल रहे इस गुप्त सट्टा अड्डे पर 6 अप्रैल 2026 को मुखबिर से मिली सटीक सूचना के बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की और मौके पर रेड मारकर तीन आरोपियों को रंगे हाथ सट्टा पट्टी लिखते और लोगों को लालच देकर सट्टा खिलाते हुए पकड़ लिया, यह पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक कांकेर निखिल अशोक कुमार राखेचा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष बंछोर के मार्गदर्शन और एसडीओपी शुभम तिवारी के पर्यवेक्षण में अंजाम दी गई जहां थाना सिकसोड़ और साइबर टीम ने संयुक्त रूप से रणनीति बनाकर घेराबंदी की और बिना मौका दिए आरोपियों को दबोच लिया, गिरफ्तार आरोपियों में राजेश बघेल पिता स्वर्गीय जयलाल बघेल उम्र 41 वर्ष निवासी करेंगांव स्कूल पारा, शेख शरीफ कुरैशी उम्र 52 वर्ष निवासी अंतागढ़ गढ़पारा और चंपालाल कोर्राम पिता स्वर्गीय श्याम सिंह उम्र 33 वर्ष निवासी करेंगांव तरियापारा शामिल हैं।

कलेक्टर ने संकल्प शिक्षण संस्थान का किया निरीक्षण

इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी कर रहे बच्चों से की चर्चा

जशपुर (समय दर्शन)। कलेक्टर रोहित व्यास ने बुधवार को संकल्प शिक्षण संस्थान का निरीक्षण करके बच्चों के शैक्षिक गतिविधियों की जानकारी ली।

उन्होंने बच्चों से छ्वश्वश्व और नीट प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की जानकारी ली और विघार्थियों को कड़ी मेहनत करके भारत के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग और मेडिकल कालेज में प्रवेश लेने के लिए प्रोत्साहित किए। कलेक्टर ने कहा अच्छी इंजीनियरिंग कालेज और मेडिकल कालेज में प्रवेश मिलने से जॉब के अच्छे अवसर मिलते हैं। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ अभिषेक कुमार, डिप्टी कलेक्टर प्रशांत कुशवाहा, संकल्प के प्राचार्य विनोद गुप्ता आर ई एस के एसडीओ अमित देव सिंह, कार्यपालन अभियंता राजेश श्रीवास्तव और अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

कलेक्टर ने संकल्प के शिक्षकों को प्रत्येक सप्ताह बच्चों का टेस्ट लेने के निर्देश दिए हैं। और पढ़ाई में कहीं समस्या आ रही है तो उनका डाउट क्लीयर करने के लिए कहा है।

कलेक्टर ने मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे बच्चों को कहा कि अच्छी तैयारी करें जिससे सभी बच्चों का शासकीय कालेज में प्रवेश मिल जाए।

उन्होंने शिक्षकों एनसीईआरटी के पुस्तक और प्रैक्टिस पेपर हल भी करवाने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर ने कहा की गर्मी की छुटियां में बच्चों को परीक्षा की तैयारी करवाए अनावश्यक छुट्टीयों में घर भेजकर उनका समय न गवाएं

पालकों को भी समझाने के निर्देश दिए हैं तीज त्यौहार में बच्चों को घर बुलाकर उनका समय खराब न करें।

कलेक्टर ने कहा कि बच्चे एक बार मेहनत करके छ्वश्वश्व और हृश्वञ्ज निकाल लेंगे तो बच्चों का भविष्य बन जाएगा।

कलेक्टर ने शिक्षकों को पुराने 9 से 10 वीं कक्षा के गणित, विज्ञान विषयों का भी रिवीजन करवाने के निर्देश दिए हैं। ताकि कोई भी विषय न छुट पाए ।

कलेक्टर ने बच्चों को गुरूप स्टडी, लाइब्रेरी का उपयोग करने के लिए कहा है।

ब्रह्माकुमारीज आनंद सरोवर बघेरा में मुख्य प्रशासिका दादी रतनमोहिनी के प्रथम पुण्यतिथि का आयोजन

दुर्ग (समय दर्शन)। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विद्यालय के बघेरा स्थित आनंद सरोवर के कमला दीदी सभागार में ब्रह्माकुमारीज की मुख्य प्रशासिका दादी रतन मोहिनी की प्रथम पुण्यतिथि का आयोजन किया गया।

उल्लेखनीय है समग्र विश्व में ब्रह्माकुमारी संस्था विश्व में ऐसी अनुपम है जहाँ के संचालन का समस्त दायित्व माताओं बहनों के हाथों में है। दादी रतन मोहिनी के जीवन यात्रा के विषय में रीटा दीदी संचालिका, ब्रह्माकुमारीज दुर्ग ने बताया। दादी रतनमोहिनी जी का जन्म 25 मार्च, 1925 को सिंध, पाकिस्तान में हुआ था। मात्र 13 साल की उम्र में वे ब्रह्माकुमारीज से जुड़ गईं और 87 वर्षों तक इस संस्था की यात्रा की साक्षी रहीं। उन्होंने अपने जीवन को अध्यात्म, सेवा और सशक्तिकरण के मार्ग पर समर्पित किया ।दादी जी की विशेषताएं में सादगी और स्नेह, दादी जी का जीवन सादगी और स्नेह से भरा था, जो उन्हें एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व बनाता था ।आध्यात्मिक ज्ञान- उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए काम किया, जिससे लोगों को जीवन के सही मार्ग पर चलने में मदद मिली ।- नारी सशक्तिकरण-वे नारी सशक्तिकरण की एक मजबूत आवाज थीं, जिन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाने के लिए काम किया। समाज सेवा-उन्होंने समाज सेवा के लिए कई कदम उठाए, जिसमें युवा प्रभाग का नेतृत्व भी शामिल है, जिससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन आया ।दादी जी की प्रेरणा। दादी रतनमोहिनी जी की प्रेरणा से अनेकों लोगों ने अपना जीवन बदल लिया। उन्होंने ब्रह्माकुमारीज के वैश्विक आंदोलन को उत्कृष्ट नेतृत्व प्रदान किया और उनकी शिक्षाएं लोगों को अध्यात्म के मार्ग पर चलने और जन-कल्याण-कार्यों के लिए प्रेरित करती रहेंगी।

इस आयोजन में ललित सेक्सरिया- (अध्यक्ष अग्रवाल समाज),पायल अग्रवाल (समाज सेविका दुर्ग) ने दादी जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि दादी जी परमात्मा के बातों को आत्मसात् कर अध्यात्म की शिखर पर पहुंची और अनेकों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी तो वास्तविक श्रद्धांजलि यही है कि हम उनके बताए हुए अध्यात्म के मार्ग का अनुसरण करें । इस आयोजन में ब्रह्माकुमारीज संस्थान के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र से अनेक भाई-बहनें उपस्थित हुए मंच संचालन ब्रह्माकुमारी रूपाली दीदी ने किया।

मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मे बंदरबाट के आरोप. गरीबो के अनुदान को भाजपा पदाधिकारियों ने डकारा

गरियाबंद (समय दर्शन)। बीते दिनों जिले में मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान कि एक लिस्ट शहर के गलियों में घूमती हुई राजिम विधानसभा से बिंद्रानवागढ़ तक पहुंच गई, जिसमें नगरसहित राजिम विधानसभा के गरीब दवे कुचले वर्ग और बीमार, अत्यंत लाचार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मुख्यमंत्री ने परोपकार करते हुए स्वेच्छानुदान जारी किया। किन्तु राजधानी से अनुदान राशि राजिम पहुँचते पहुँचते भाजपा पार्टी के पदाधिकारिओ के नाम ई सरकारी अनुदान लिस्ट मे निकल आये। भाजपा के पदाधिकारियो ने आपस मे ही बाट कर एक बार फ्रि साबित कर दिया कि पार्टी को गरीब बेबस लाचार जनता से कोई लेना देना नहीं है ज़ब भी मौका मिलेगा तो पहले खुद ही सरकारी धन का आपस मे बटवारा करेंगे फ्रि बचा कुचा आम जनो के हिस्से मे आएगा । जो प्रदेश कि राजनितिक व्यवस्था मे गंभीर सवाल खडे करते है वंही राजनैतिक दायित्व मर्यादा सेवा भाव को अपने लाभ के लिए तिलाँजली देने जैसा है। स्वेच्छानुदान लिस्ट मे नाम देख नगर सहित राजिम विधानसभा के लोग हैरान रह गए और अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह तो भाजपा के कार्यकर्ताओ को एक वर्ष मे मिलने वाले बोनस कि तरह लग रहा है। लोगो ने बताया कि जिनके नाम इस अनुदान लिस्ट मे शामिल किये गए है वह लोग गरीबो के अधिकार पर प्रहार है। इसलिस्ट मे इनकम टैक्स पेयी से लेकर गांव के दाऊ तक के नाम शामिल किये गए है। दरअसल स्वेच्छानुदान लिए पात्र ही वह व्यक्ति होता है जो गरीब लाचार बेबस हो, तत्काल कुछ रुपयों कि जरूरत हो, पर लिस्ट देखने के बाद ऐसा नहीं लगता. इसमें भाजपा के मंडल अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष तक भाजपा के पदाधिकारी शामिल है ।

जिले मे सरपंच पूर्व सरपंच जनपद सदस्य, पार्टी पदाधिकारीयों, भाजपा पार्षद , भाजपा पार्षद पति,भाजपा के पूर्व एल्डर मैन तक का नाम शामिल है ।भाजपा के मंडल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, सभी पदाधिकारियों को 10 हजार बुथ अध्यक्षों को 5 हजार वंही कई व्यक्तिओ के नाम डबल, तो कंही पति पत्नी दोनों को मिला स्वेच्छानुदान प्राप्त हुआ है ,सरकारी नौकरी करने वाले पति के पत्नी को भी शामिल किया गया है. लिस्ट बनाने वाले पार्टी नेता ने भी किया अपने ही पार्टी कार्यकर्ताओ से भेदभाव, अपने परिवार के लोगो को किया शामिल, वंही बिंद्रानवागढ़ विधानसभा के भाजपा कार्यकर्ताओ मे रोश है कि उनको इस सरकारी लिस्ट मे शामिल नहीं किया गया। वह भी तो भाजपा का झंडा बुलंद कर रहे है। आखिर मुख्यमंत्री जी ने ऐशा भेदभाव क्यू किया। कुछ गैरत मंद कार्यकर्ताओ ने इस राशि को लेने से ही इंकार कर दिया, पर इनकी गिनती उंगलियों मे है।

खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर की गई कार्रवाई

जांजगीर चांपा (समय दर्शन)। कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे के निर्देशन में जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर रोकथाम हेतु राजस्व, पुलिस एवं खनिज विभाग द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए जिले के विभिन्न क्षेत्रों में खनिजो के अवैध परिवहन, भण्डारण, उत्खनन औचक जांच किया गया। खनिह्ल अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान बलौदा विकासखंड के ग्राम केराकछार में रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 07 ट्रैक्टर, 02 टीपर एवं 01 हाईवा को जब्त कर पंतोरा चौकी के सुपुर्द किया गया तथा 02 टीपर को मौके पर ही नोटिस चस्पा कर सील किया गया। इसी क्रम में चांपा क्षेत्र में अवैध रेत परिवहन करते पाए जाने पर 01 ट्रैक्टर को जब्त कर चांपा थाना के सुपुर्द किया गया। हथनेवरा में जांच के दौरान 04 हाईवा जब्त किए गए, वहीं ग्राम पिपरदा में भी मौके पर 04 हाईवा जब्त किए गए। इसके अतिरिक्त अवैध रेत परिवहन में संलिप्त पाए गए 03 हाईवा को जब्त कर पुलिस लाइन खोखरा में सुरक्षार्थ रखा गया है। खनिजों के अवैध परिवहन के दर्ज प्रकरणों पर अवैध परिवहनकर्ताओं के विरूद्ध खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 से 23 (ख) के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर श्री महोबे के निर्देशन में जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण के संबंध में खनिज विभाग द्वारा निरंतर जांच कार्यवाही की जा रही है, जो कि आगे भी इसी प्रकार जारी रहेगी।

नक्सली मुक्त होने के बाद नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहे,ग्रामीणों के बीच पहुंचकर भाजपा जिला अध्यक्ष ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धि गिनाई

गरियाबंद (समय दर्शन)। भाजपा के स्थापना दिवस को लेकर गांव बस्ती चलो अभियान अंतर्गत भाजपा जिला अध्यक्ष अनिल चंद्राकर ने नक्सली मुक्त होने के बाद नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहे दर्रीपारा के अनेक ग्रामों का दौरा कर सीधे ग्रामीणों से चर्चा की गांव की मूलभूत समस्या सुनी ।इसके अलावा केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। अनेक योजनाओं के लाभान्वित हितग्राहियों ने चर्चा के दौरान केंद्र और राज्य सरकार की संचालित योजनाओं के लाभ मिलने पर प्रसन्नता जाहिर की। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत अभियान की तरफदेश आगे बढ़ रहा है ।उनके साथ दौर में भाजपा जिला मंत्री सुरेंद्र सोनटेके, बिंद्रानवागढ़ भाजपा मंडल अध्यक्ष धनराज विश्वकर्मा,मंडल महामंत्री धनंजय नेताम ,त्रिलोक राठौर मौजूद थे।

भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्राकर ने ग्राम दर्रीपारा और रावण डिग्गी में ग्रामीणों को संबोधन में कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गांव गरीब और किसानों के विकास के लिए संकल्पित है ।केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धि यह है कि तेजी से विकास कार्य हो रहा है ।विकास के मामले में गांव और शहर की तस्वीर बदल रही है ।कहा कि शासन की योजना कल आप सीधे लोगों को मिल रहा है ।प्रधानमंत्री आवास,किसान सम्मान निधि के अलावा केंद्र सरकार की सैकड़ो योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को सीधे मिल रहा है ।वहीं राज्य की भाजपा सरकार मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सुशासन की सरकार छत्तीसगढ़ में लाने में सफ्ल हुई है। महतारी वंदन की राशि प्रत्येक माह महिलाओं को मिल रही है ।वही भाजपा जिला मंत्री सुरेंद्र सोनटेके,मंडल अध्यक्ष धनराज विश्वकर्मा ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है। चुनाव के दौरान मोदी की गारंटी पूरा करने का वायदा सरकार ने किया था ।उसी के तहत कार्य किया जा रहे हैं ।जी राम जी योजना से गांव विकास से खुशहाल होगा। उल्लेखनीय है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में चुनाव के बाद भाजपा नेताओं ने दौरा किया। ग्रामीणों ने बताया कि राज्य राशन प्रत्येक माह मिल रहा है ।इस अवसर पर मुकेश बिसेन,प्रीतम प्रधान, बरातुराम ध्रुव,भूपेंद्र ध्रुव,रमेश ध्रुव,अघन सिंह ठाकुर,भादूराम ध्रुव,ललित ध्रुव,रूपेशध्रुव ,गिरधारी ध्रुव,गणेशराम ध्रुव,बलराम देवांगन, प्रहलाद ठाकुर एवं ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

कलेटर ने की जल संचय, जन भागीदारी अभियान 2.0 के कार्यों की प्रगति की समीक्षा

बालोद (समय दर्शन)। कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने संयुक्त जिला कार्यालय सभाकक्ष में मंगलवार 07 अप्रैल को विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में जल संचय, जन भागीदारी अभियान 2.0 के कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को बालोद जिले में 31 मई तक अधिक से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण कर जेएसजेबी पोर्टल में उसका शत प्रतिशत एंट्री करने के निर्देश दिए। बैठक में श्रीमती मिश्रा ने बारी-बारी से विभागवार निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगतिरत एवं पूर्ण जल संरचनाओं के निर्माण के संबंध में जानकारी ली। बैठक में श्रीमती मिश्रा ने शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग, खाद्य, सहकारिता आदि विभागों के अधिकारियों के अलावा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारियों से अपने-अपने विभागों के अंतर्गत जल संरचनाओं के निर्माण के संबंध में जानकारी ली। श्रीमती मिश्रा ने सभी अधिकारियों को इस कार्य को विशेष प्राथमिकता देते हुए निर्धारित समयावधि में पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील चंद्रवंशी, अपर कलेक्टर श्री चंद्रकांत कौशिक, जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता श्री पीयूष देवांगन सहित लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के कार्यपालन अभियंताओं के अलावा विभिन्न अधिकारीगण उपस्थित थे।

राजस्व परववाड़ा अंतर्गत गुरूर एवं डौण्डीलोहारा अनुविभाग के राजस्व ग्रामों में नियमित रूप से शिविर आयोजित

बालोद (समय दर्शन)। राज्य शासन के निर्देशानुसार संपूर्ण बालोद जिले की भाँति जिले के राजस्व अनुविभाग गुरूर एवं डौण्डीलोहारा के राजस्व ग्रामों में भी नियमित रूप से 01 अप्रैल से प्रारंभ राजस्व पखवाड़ा के अंतर्गत शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान शिविरों में आम नागरिकों के नामांतरण, बटवारा, नक्शा सुधार, त्रुटि सुधार, आय, जाति, निवास एवं अन्य राजस्व प्रकरणो से संबधित आवेदन स्वीकार किये जा रहे है तथा पात्र प्रकरणों का मौके पर ही निराकरण किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि राजस्व पखवाड़ा के अंतर्गत तीन महिनों में 01 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026, 04 मई से 18 मई 2026 तथा 01 जून से 15 जून 2026 तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा। शिविरों की सूचना संबंधित ग्रामों में मुनादी एवं अन्य माध्यमो से पूर्व में दी जाएगी जिससे अधिक से अधिक ग्रामीण जन शिविर का लाभ उठा सकें। राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों द्वारा समस्त नागरिको से अपील की गई कि वे अपने लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण हेतु निर्धारित तिथियों में आयोजित शिविरो में उपस्थित होकर शासन की इस जन हितकारी पहल की लाभ उठाने की अपील की जा रही है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गुरूर श्री रामकुमार सोनकर ने बताया कि आम नागरिकों को शिविर आयोजन की सूचना मुनादी एवं अन्य माध्यमों से नियमित रूप से दी जा रही है। इसी तरह अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डौण्डीलोहारा श्री शिवनाथ बघेल ने बताया कि डौण्डीलोहारा अनुविभाग में राजस्व पखवाड़ा का सफ्ल आयोजन सुनिश्चित करने हेतु उनके साथ-साथ तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं अन्य अधिकारियों के द्वारा नियमित रूप से शिविरों का विजिट कर शिविर में प्राप्त आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है।

कार्यालय नगर पालिक निगम, रिसाली
रिसाली सेक्टर बी.एस.पी. स्कूल नं.-35, पिन-490006
Website:-risall.urbanecg.gov.in

क्र./ लो.क.वि./2026/35 रिसाली, दिनांक 7/4/26

/ / निविदा सूचना //

निगम, रिसाली की ओर से निम्नलिखित कार्यों हेतु लोक कर्म विभाग में एकीकृत पंजीयन प्रणाली में सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारो से लो.क.वि. भवन एसओआर 01.01.2015 के आधार पर प्रतिशत दर पर निविदा आमंत्रित की जाती है :-

क्रं.	कार्य का नाम	लागत (लाख में) रू.
1	वार्ड क्र. 06 रूआबांधा सेक्टर गणेश मैदान में बोर खनन कार्य (पार्षद निधि)	1.50
2	वार्ड क्र. 05 एच.एस.सी.एल कालोनी ब्लॉक नं. 98/ए मैदान में एवं माया नगर बी.एस.एन.एल कालोनी के सामने बोर खनन कार्य (पार्षद निधि)	2.00

नियम एवं शर्तें तथा कार्यो का विस्तृत विवरण संचालनालय की वेबसाईट www.uad.cg.gov.in में देखी जा सकती है।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम,
रिसाली

3मई को प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी का प्रदेश स्तरीय वार्षिक आमसभा

प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा उपरांत प्रस्ताव पारित

रायपुर (समय दर्शन)। प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के प्रदेश प्रबंध कार्यकारिणी एवं जिला अध्यक्षों का आवश्यक बैठक राजधानी रायपुर के न्यू राजेंद्र नगर गुरु घासीदास संस्कृतिक भवन में संपन्न हुआ। प्रदेश अध्यक्ष एल एल कोसले जी के अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश स्तरीय मासिक बैठक में प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के संगठन विस्तार सहित विभिन्न विषयों पर जिला वार समीक्षा करके प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दिया गया। बैठक के प्रमुख एजेंडा में प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज द्वारा राजधानी रायपुर में एक करोड़ से अधिक के लागत पर बनने वाले बहुद्देशीय भवन सह प्रगतिशील के प्रदेश कार्यालय के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया। शासन से प्राप्त एक करोड़ राशि से अतिशीघ्र बहुद्देशीय भवन निर्माण करने तथा भविष्य के लिए सिटी कार्यालय के लिए भी जमीन खरीदी पर सहमति बनी। प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज की वार्षिक आमसभा 3 मई 2026 को रखा गया है। जिसमें पिछले वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट आय-व्यय की जानकारी, सतनाम धर्मशाला की आय व्यय सहित प्रदेश कार्यालय एवं पत्रिका प्रकाशन एवं वितरण में आय व्यय सहित साल भर में किए गए गतिविधियों की जानकारी दिए जाऐंगे। जिसके लिए सर्वसम्मति से 3 मई की तिथि तय की गई है उक्त आमसभा सतनाम धर्मशाला मडवा में आयोजित किया जाना प्रस्तावित किया गया है जिसमें प्रदेश भर से प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के प्रदेश पदाधिकारी, आजीवन सदस्य एवं सामान्य सदस्यों सहित संरक्षक एवं विभिन्न जिला के जिला एवं ब्लाक अध्यक्षो एवं पदाधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने अपील किया गया है। संगठन विस्तार के तहत जिला बेमेतरा ,महासमुंद ,रायगढ़, मुंगेली ,गरियाबंद , कबीरधाम सहित दुर्ग एवं बस्तर संभाग में अप्रैल व मई 2026 के अंत तक हर हाल में संगठन विस्तार करने का निर्देश दिया गया है। उनके लिए युवा प्रकोष्ठ ,महिला प्रकोष्ठ तथा सीनियर पदाधिकारी को प्रभार एवं जिम्मेदारी दी गई है। शासन से अनुमति मिलते ही प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के प्रदेश कार्यालय भवन गोगांव रायपुर में निर्माण कराए जाने पर आम सहमति बनी है। नया राजधानी रायपुर के पूर्व में प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतमी समाज के जमीन पर सामाजिक तत्वों द्वारा की जा रही धांधली के लिए कमेटी बनाकर संबंधित के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का निर्णय लिया गया है इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। बलौदा बाजार मामले में सैकड़ो निर्दोष लोगों की समस्या के समाधान हेतु राज्य सरकार से सकारात्मक चर्चा एवं पहल करने का निर्णय लिया गया है। वार्षिक आमसभा के लिए एजेंडा पर चर्चा किया गया। तथा प्रदेश पदाधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है।

बैठक में प्रमुख रूप से प्रदेश अध्यक्ष एल एल कोसले ,प्रदेश उपाध्यक्ष सुशील सोनवानी प्रदेश कोषाध्यक्ष श्याम टांडे, प्रदेश महासचिव मोहन बंजारे, प्रदेश सचिव दिनेश बंजारे ,प्रदेश प्रवक्ता राजमोहन, पी एल कोसरिया,महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष सुश्री अंजली बरमाल , प्रदेश कार्यकारिणी एस आर बंजारे, गुलाब टंडन यादराम हिरवानी,सत्येंद्र खूंटे, श्रीमती द्रौपदी जोशी ,श्रीमती निशा ओगरे, श्रीमती रजनी डांडे, अनिता गुरुपंच ,प्रदेश उपाध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ दिनेश लहरे, प्रदेश महासचिव अशोक बंजारे रायपुर शहर जिला अध्यक्ष मनोज बंजारे, ग्रामीण जिला अध्यक्ष रमेश बंजारे,तिलोकचंद खरे,रवि मिरी रंजीत,गायकवाड़,,संतोष कोसरिया,बेमेतरा जिला अध्यक्ष राजा लाल, सारंगढ़ बिलाईगढ़ के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष गिरवर निराला,लेखराम खडबंदे घरघोडा,मनोज डांडे,राधेश्याम डांडे,,चन्द्रप्रभा, कुर्रे,श्रीमती शकुन्तला डांगे,मंजूषा पाटले, गणपत बंजारे,प्रेमदास,खिलेश्वर, सत्यनरारायण,एड.किशोर टण्डन,संदीप खरे,अजय साण्डे,मोतीलाल भारती,जागेश्वर कुर्रे सहित प्रमुख पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। यह जानकारी प्रगतिशील छ ग सतनामी समाज प्रदेश सचिव दिनेश बंजारे ने दी।

संक्षिप्त-खबर

9 भारतीय विशाल गिलहरियों के शिकार मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार

गरियाबंद (समय दर्शन)। उदंती सीता नदी टाइगर रिज़र्व की टीम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 9 दुर्लभ गिलहरियों के शिकारी को गिरफ्तार किया साथ ही आरोपियों के घर से भालू की खाल और फंदे बरामद किए वही फरार शिकारियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

मामले का खुलासा तब हुआ जब ओडिशा वन कर्मचारियों को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो रील मिली जिसमें दो लोग दुर्लभ भारतीय विशाल गिलहरियों के साथ नजर आ रहे थे। यह प्रजाति वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत अनुसूची-1 में संरक्षित है।इस खबर पर तुरंत एक्शन लेते हुए उदंती सीता नदी टाइगर रिज़र्व की एंटी-पोचिंग यूनिट, राज्य फ्लाइंग स्क्वाड और दंतेवाड़ा वन विभाग की संयुक्त टीम ने जांच शुरू की। इंस्टाग्राम रील्स की लोकेशन ट्रैक कर 8 अप्रैल 2026 को बारसूर क्षेत्र से आरोपी बंशीराम कोवासी को गिरफ्तार कर लिया गया।तलाशी के दौरान आरोपी के घर से स्लॉथ भालू की खाल और शिकार में इस्तेमाल होने वाले फंदे भी बरामद किए गए। शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी झाड़ी-मांस (बुश मीट) के लिए वन्यजीवों का शिकार करता था। अन्य फरार आरोपियों पर नजर रखी जा रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक भारतीय विशाल गिलहरी जंगलों के लिए बेहद अहम प्रजाति है, जो बीज फैलाकर पेड़ों के पुनर्जनन में मदद करती है। इसकी मौजूदगी स्वस्थ वन तंत्र का संकेत मानी जाती है। वन विभाग ने साफ किया है कि अवैध शिकार और वन्यजीव तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और आम लोगों से भी ऐसी गतिविधियों की सूचना देने की अपील की गई है।

आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु आवेदन आमंत्रित, 23 तक करें ऑनलाइन आवेदन

बेमेतरा (समय दर्शन)। कार्यालय परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना बेमेतरा द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों में रिक्त आंगनबाड़ी सहायिका पदों पर भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह भर्ती छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्धारित नियमों एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाएगी। इच्छुक एवं पात्र महिला अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। जारी विज्ञापन के अनुसार नगर पालिका बेमेतरा अंतर्गत वार्ड क्रमांक 08 (कोदवा/ओमकार्ड वार्ड) में आंगनबाड़ी सहायिका का एक पद रिक्त है, जिसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है, जिसके लिए अभ्यर्थियों को विभागीय पोर्टल द्धह्लह्लश्च-ह्य://222.द्ग-ड्डद्धड्डह्लह्द्ध.द्दश्र/ के माध्यम से पंजीयन कर आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है।

निर्धारित कार्यक्रम के तहत प्राप्त आवेदनों की जांच, सत्यापन एवं चयन प्रक्रिया विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाएगी। अंतिम चयन सूची जारी होने के पश्चात ही अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। आंगनबाड़ी सहायिका पद के लिए अभ्यर्थी का संबंधित ग्राम/वार्ड का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। केवल महिलाओं को ही इस पद हेतु पात्र माना गया है। आवेदिका की अधिकतम आयु सीमा 44 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि विधवा, परित्यक्ता अथवा अन्य विशेष श्रेणी की महिलाओं को नियमानुसार आयु में छूट प्रदान की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता के रूप में न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यदि योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो शिथिल मानदंड के तहत 5वीं पास अभ्यर्थियों पर भी विचार किया जा सकता है।

चयन प्रक्रिया में अनुभव, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार, अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग, विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिलाओं को नियमानुसार अतिरिक्त अंक प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा संबंधित क्षेत्र में निवास एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों का सत्यापन अनिवार्य होगा।

आवेदन के साथ अभ्यर्थियों को शैक्षणिक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), गरीबी रेखा संबंधी प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना होगा। सभी दस्तावेज स्वप्रमाणित होना अनिवार्य है।प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जाएगी। इसके पश्चात दावा-आपत्ति आमंत्रित कर उनका निराकरण किया जाएगा तथा अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी।

कर्मयोगी भारत के अंतर्गत राष्ट्रीय अधिगम सप्ताह (साधना सप्ताह 2026) के लिए जिले में तैयारी तेज

कलेक्टर बीएस उइके ने अधिकारियों की बैठक लेकर दिए आवश्यक निर्देश

गरियाबंद (समय दर्शन)। जिले में कर्मयोगी भारत के अंतर्गत राष्ट्रीय अधिगम सप्ताह (साधना सप्ताह 2026) के अंतर्गत कलेक्टर बीएस उइके की अध्यक्षता में अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। कलेक्टर ने सभी अधिकारी-कर्मचारियों को निर्देशित किया कि कर्मयोगी के तहत साधना सप्ताह को प्रभावी रूप से क्रियान्वयन के लिए अपने-अपने स्तर पर सभी आवश्यक कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करें।

उल्लेखनीय है कि 2 अप्रैल से 10 अप्रैल 2026 तक यह विशेष अधिगम अभियान आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों में समन्वित, समयबद्ध तथा केन्द्रित अधिगम विकसित करना है, ताकि प्रशासनिक कार्यक्षमता में और अधिक सुधार हो सके।इस दौरान एनआईसी के उपनिदेशक श्री नेहरू निराला ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से सभी अधिकारी-कर्मचारी को प्रत्येक बारीकियों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया और उनके समस्याओं का समाधान भी बताया।

उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण सभी अधिकारी-कर्मचारी के लिए आवश्यक है।कलेक्टर ने कहा कि अधीनस्थ अधिकारी व कर्मचारी निर्धारित अवधि में आईजीओटी कर्मयोगी पर कम से कम 4 घंटे का अधिगम पूर्ण कर उसका प्रमाण-पत्र प्राप्त करें।साथ ही प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी को उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से कम से कम एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित पाठ्यक्रम का अध्ययन अनिवार्य रूप से करना होगा।

उन्होंने अपने-अपने विभागीय स्तर पर प्रचार-प्रसार एवं प्रेरणात्मक गतिविधियाँ आयोजित करें। इस दौरान आयोजित सेमिनार, प्रशिक्षण तथा अन्य गतिविधियों के वीडियो क्लिप को अनिवार्य रूप से आईजीओटी पोर्टल पर अपलोड करें। तकनीकी सहायता की आवश्यकता होने पर संबंधित शाखाओं को पोर्टल पर उपलब्ध तकनीकी सपोर्ट टीम से संपर्क कर आवश्यक जानकारी लें। इसी प्रकार, आईजीओटी प्लेटफॉर्म के डैशबोर्ड के माध्यम से अधिगम की प्रगति की नियमित निगरानी संबंधित नोडल अधिकारियों द्वारा की जाएगी।

कलेक्टर ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों कहा कि वे इस अधिगम सप्ताह में सक्रिय भागीदारी कर अपने कौशल एवं दक्षता में वृद्धि कर बेहतर प्रशासनिक सेवा प्रदान करने की दिशा में योगदान दें। इस दौरान अपर कलेक्टर पंकज डाहिरे,जिला व्यापार एवं उद्योग विभाग के महाप्रबंधक दीनबंधु ध्रुव, पंचायत विभाग के उप संचालक पद्मनी हरदेव, अंत्यावसायी के कार्यपालन अधिकारी रश्मि गुप्ता सहित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

मोतीपुर में शुरू हुई प्याऊ घर सेवा, राहगीरों को मिलेगा शीतल जल

राजनांदगांव (समय दर्शन)। महर्षि वाग्भट्ट गौ संवर्धन एवं अनुसंधान संस्थान ने आजाद चौक मोतीपुर स्थित हनुमान मंदिर और ढाबा रोड स्थित भोलेनाथ मंदिर में प्याऊ घर सेवा का शुभारंभ किया। इस मौके पर संस्थान के अध्यक्ष राधेश्याम गुप्ता और समाजसेवी शिव वर्मा ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और मटकों पर राम नाम अंकित किया।

राधेश्याम गुप्ता ने कहा कि भारतीय संस्कृति में जल दान को सर्वोत्तम दान माना गया है। भीषण गर्मी में राहगीरों, जरूरतमंदों और आमजन को शीतल जल उपलब्ध कराना पुण्य का कार्य है। उन्होंने मटके के पानी के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यह प्राकृतिक रूप से ठंडा, स्वास्थ्यवर्धक और पर्यावरण के अनुकूल होता है, जबकि बोतलबंद और अत्यधिक ठंडा पानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है।

समाजसेवी शिव वर्मा ने बताया कि प्याऊ घर सेवा केवल जल उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानवता और सहयोग की भावना को भी बढ़ावा देती है। संस्थान के सदस्य धर्मराज यादव ने कहा कि शिव शक्ति धर्मार्थ सार्वजनिक सेवा समिति, चिखली द्वारा नि:शुल्क मटकों की व्यवस्था की गई है। सेवा पूरे ग्रीष्मकाल में निरंतर जारी रहेगी, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।

इस दौरान राहगीरों को शीतल जल के साथ शर्बत भी वितरित किया गया। कार्यक्रम में जीआर देवांगन, नरेन्द्र देवांगन, पुरूषोत्तम देवांगन, शिक्षा संस्कार पाठशाला के छात्र और वार्डवासी उपस्थित रहे।

प्याऊ घर सेवा से मोतीपुर क्षेत्र में राहगीरों और स्थानीय लोगों को गर्मी में राहत मिलने की उम्मीद है।

खनिज विभाग की कार्यवाही,3 चैन माउंटेन और रेत से भरी हाईवा जब्त

गरियाबंद (समय दर्शन)। जिले में रेत माफियाओं पर खनिज विभाग ने तगड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध कारोबार की कमर तोड़ दी है। कलेक्टर भगवान दास उइके के सख्त निर्देश और मार्गदर्शन में चल रही कार्रवाई के तहत खनिज विभाग ने बड़ी दबिश दी। सहायक खनिज अधिकारी अर्चना ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि टीम ने अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए 3 चैन माउंटेन और 1 रेत से भरी हाईवा जब्त की है। जिसमे बरौंडा क्षेत्र से 2 चैन माउंटेन जब्त, चोबेबंधा से 1 चैन माउंटेन पकड़ी गई।

वहां 3 चैन माउंटेन को पांडुका थाने में खड़ा कराया गया,साथ ही रेत से भरी हाईवा को राजिम थाने में जब्त कर रखा गया है।खनिज विभाग की इस कार्रवाई से अवैध रेत के कारोबार करने वालो में हड़कंप मच गया है। लगातार हो रही सख्ती से साफसंकेत है कि अब अवैध रेत कारोबार पर शिकंजा और कसने वाला है।

चौकी भंवरपुर थाना बसना पुलिस की कार्यवाही, जुआ फड़ में पुलिस की रेड

09 जुआरियों के विरूद्ध की गई जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही

ग्राम बनडबरी से संतपाली मार्ग नीम पेड़ के नीचे चल रहा था जुआ का फड़

बसना(समय दर्शन)। महासमुन्द जिला क्षेत्रांतर्गत बसना थाना के भंवरपुर चौकी अंतर्गत के ग्राम बनडबरी में पुलिस ने जुआ फड़ पर रेड मारकर 9 जुआरियों को रंगे हाथों पकड़ा है। महासमुन्द पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार एवं एसडीओपी ललीता मेहर द्वारा असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने की दिशानिर्देश के परिपालन में बसना थाना प्रभारी शरद दुबे के कुशल रणनीति तथा भंवरपुर चौकी प्रभारी राणासिंह ठाकुर एवं पुलिस टीम की सजगता से अपराधियों को धर दबोचने में सफलता मिली।जिस पर आरोपियों के विरुद्ध पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई है। जानकारी के अनुसार दिनांक 07/04/26 को जरिये मुखबीर से सूचना मिला कि, कुछ व्यक्ति ग्राम बनडबरी से संतपाली जाने वाली कच्चा रास्ता, नीम पेड के पास, ग्राम -बनडबरी (क) में 52 पत्ती तास से रूपये पैसे का दाव लगाकर काट पत्ती नामक जुआ खेल रहे है कि उक्त सुचना पर मुखबीर पंचनामा तैयार कर गवाह वा हमराह स्टाफके मुखबीर के बताये स्थान पर रेड कार्यवाही किया जिसमें 09 जुआडियान को 52 पत्ती तास से रूपये पैसे का हार जीत दाव लगाकर काट पत्ती नामक जुआ खेलते रंगे हाथ पकडे।

जुआ खेलने वाले के पास से एवं फंड से नकदी रकम 12300/-एवं 08 नग मोबाईल किमती 30000/- एवं 06 नग मो.सा. पुरानी ईस्तमाली किमती 94000 /- एवं 52 पत्ती तास एवं सफेद कलर की प्लास्टिक बोरी कुल जुमला किमती 1,36,300/- रूपये गवाह के समक्ष मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया । जुआडियानों का कृत्य 13 जुआ एक्ट, 3(2) छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधि. 2022 का पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

छत्तीसगढ़ के निजी मेडिकल कॉलेजों के 50 प्रतिशत सीटों को सेमी गवर्मेंट सीट में तब्दील करने की मांग

छत्तीसगढ़िया सर्व समाज ने मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री के नाम पर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

महासमुन्द (समय दर्शन)। छत्तीसगढ़िया सर्व समाज एससी-एसटी ओबीसी महासंघ महासमुन्द ने मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री से छत्तीसगढ़ के सभी निजी मेडिकल कालेजों में 40-50 प्रतिशत सीटों को सेमी गवर्मेंट सीट में तब्दील कर राज्य के मुलनिवासी छात्रों को राहत देने की मांग करते हुए कलेक्टर महासमुंद को ज्ञापन सौंपा है।

ज्ञापन में बताया है कि छत्तीसगढ़ में शासकीय मेडिकल कॉलेज के अलावा पांच निजी कालेज संचालित हैं।शासकीय कालेजों की फीस कम होने के कारण सभी वर्ग के लोग आसानी से एडमिशन लें लेते हैं, लेकिन निजी कालेजों में राज्य के कोटा सीटों की फीस भी भारी-भरकम है, जिससे एससी-एसटी ओबीसी वर्ग के छात्र एडमिशन नहीं ले पाते हैं,, और बाद में खाली सीटें ओपन सीट में तब्दील हो जाती है। जिस पर बाहरी राज्य के साधन सम्पन्न छात्र पढ़ाई करके अपने राज्य चलें जातें हैं,,या फिर राज्य के अमीर तबके के लोग मोटी रकम से पढ़ाई करने के बाद अपनी प्राइवेट कालेज खोल लेते हैं,, जिसके कारण छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी बनी हुई है। जबकि देश के आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, तेलांगना, हरियाणा, पंजाब , तमिलनाडु जैसे अन्य राज्यों में निजी मेडिकल कॉलेज में राज्य कोटे की सीट पर सेमी गवर्मेंट सीट की व्यवस्था है ,,जिसमें उस राज्य के मुलनिवासी छात्र कम फीस पर एडमिशन लें सकते।

चुंकि सेमी गवर्मेंट फीस को राज्य सरकारें वहन करतीं हैं। चुंकि छत्तीसगढ़ राज्य एससी एसटी ओबीसी बाहुल्य राज्य है जहां ज्यादातर छात्रों के पालक कृषक मजदूर हैं और छोटे कर्मचारी हैं जो निजी कालेज के फीस भर पाने में असमर्थ होते हैं। इसलिए अन्य राज्यों की भांति छत्तीसगढ़ में सभी निजी कालेज के कुल सीट के 40 से 50 प्रतिशत सीटों को सेमी गवर्मेंट सीट के तहत राज्य के मुलनिवासी छात्रों को एडमिशन देकर राहत दी जाएं जिससे यहां के छात्र डॉक्टर की डिग्री लेने के बाद भी राज्य के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में सेवा देकर डॉक्टरों की कमी को पूर्ण कर सकें। सेमी गवर्मेंट सीट से पढ़ाई करने वाले छात्रों को निश्चित अवधि तक सरकारी अस्पतालों में सेवा देने की अनुबंध भी रहतीं हैं।

ज्ञापन देने वालों में मुन्ना साहु प्रदेश सचिव, बसंत सिन्हा जिलाध्यक्ष,एच आर बघेल, एसपी ध्रुव सरंक्षणद्वय, दिनेश बंजारे सलाहकार, राजेश डड़सेना विधि सलाहकार, विजय बंजारे कार्यकारी जिलाध्यक्ष,भुपेंद्र चंद्राकर, द्रोण चंद्राकर उपाध्यक्ष,रेखराम बघेल महामंत्री, सुरेन्द्र ठाकुर,खिलावन साहु, कल्पनासुर्यवंशी संगठन मंत्री, दिनेश कुमार साहू सरपंच संघ अध्यक्ष,कुमार यादव, संतोष डहरिया, पुनाराम निषाद, भोलाराम निषाद, राजेश रात्रे, कुमार यादव,सुनील निषाद, केशवराम चंद्राकर , ओमप्रकाश पटेल संगठन मंत्री,एच आर सोनवानी, आनन्द कुर्रे, चिंता कुर्रे व अन्य लोग शामिल रहे, उक्त जानकारी जिला मीडिया प्रभारी सोमनाथ टोंडेकर दी।

निधन : राजेन्द्र श्रीवास्तव

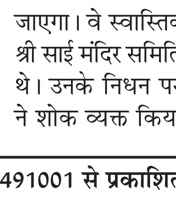

दुर्ग। पद्मनाभपुर लाला हॉउस एमआईजी-42 निवासी राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव का बुधवार को निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार 9 अप्रैल, गुरुवार को सुबह 9 बजे शिवनाथ नदी मुक्तिधाम में किया जाएगा। वे स्वास्तिक इंडस्ट्रियल एंड के डायरेक्टर और श्री साई मंदिर समिति सिविल लाइन कसारीडीह के सदस्य थे। उनके निधन पर श्री साई मंदिर समिति के सदस्यों ने शोक व्यक्त किया है।

स्वामित्वधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक रोहित खड़तकर द्वारा समय दर्शन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स ग्राम छाटा, पोस्ट देवादा, तहसील पाटन, जिला दुर्ग (छ.ग.) 491111 से मुद्रित कर बी-4, प्रेस काम्प्लेक्स, इंदिरा मार्केट, दुर्ग छ.ग. 491001 से प्रकाशित। संपादक :- रोहित खड़तकर,
समाचार संपादक : दामोदर राव, फोन नं.-0788-4051213, मो. 9827104452, रायपुर कार्यालय:-0771-4218364, ईमेल - samay.darshan191@gmail.com पं. क्र. CHHHIN/2011/41517 डाक पंजीयन क्रमांक छ.ग./दुर्ग/61/2024-26